आज का विचार

किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाए बिना जीना... संसार का ऐसा सुंदर कर्म कोई और नहीं है।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ I शनिवार, 11 अप्रैल, 2026 वर्ष 24, अंक 87, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं की लिफ्टिंग के लिए विशेष रेल गाड़ियां चलाई जाएंगी: मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से मुलाकात की, किसानों और मंडियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर राहत और ठोस कदम सुनिश्चित किए

सिटी दर्पण संवाददाता

नई दिल्ली

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्राद जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य के किसानों और मंडियों के लिए कई महत्वपूर्ण राहत उपाय सुनिश्चित किए। इस दौरान केंद्र ने पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग के लिए विशेष रेल गाड़ियां चलाने पर सहमति दे दी, जिससे रबी मंडीकरण सीजन से पहले राज्य में अनाज भंडारण संबंधी गंभीर संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस हस्तक्षेप के साथ-साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पर बोझ बने संरचनात्मक मुद्दों के समाधान पर जोर दिया, जिसमें उच्च नकद ऋण ब्याज दरें, ग्रामीण विकास फंड के तहत लंबित 9,000 करोड़ रुपए, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा और आढ़तियों की लंबे समय से लंबित मांगें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए सचिव स्तरीय व्यवस्था बनाने सहित ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया।

एक्स हैंडल पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहाआज दिल्ली में मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्राद जोशी जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान हमने आढ़तियों की मांगों सहित पंजाब से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा: बैठक के दौरान केंद्र के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिसमें पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की तुरंत लिफ्टिंग तथा आरडीएफ के तहत बकाया 9,000 करोड़ रुपए की तुरंत अदायगी के मुद्दे शामिल थे। इसके साथ ही, नकद ऋण सीमा के तहत राज्यों पर लगाई गई उच्च ब्याज दरों को कम करने और आढ़तियों की केंद्र से संबंधित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा, मंडी मजदूरों के ईपीएफ से संबंधित मुद्दों को तुरंत हल करने की अपील की गई और असामयिक बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई।

उन्होंने आगे लिखा, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि केंद्रीय मंत्री जी ने इन सभी मुद्दों पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हम पंजाब के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। फसलों के भंडारण संबंधी भारी कमी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, राज्य के कवरड गोदामों में 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज (151.20 लाख मीट्रिक टन चावल और 29.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं) पहले से ही स्टोर किया गया है, जबकि कुल उपलब्ध कवरड भंडारण क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन (173 लाख मीट्रिक टन कवरड गोदाम + 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं साइलो) है। नतीजतन, चावलों के लिए केवल 0.50 लाख मीट्रिक टन कवरड स्पेस और गेहूं के लिए 1.75 लाख मीट्रिक टन साइलो स्पेस उपलब्ध है। उन्होंने कहा, राज्य में 1 अप्रैल, 2026 से रबी मंडीकरण सीजन (आरएमएस) 2026-27 शुरू हो गया है, जिसमें संभावित रूप से 130-132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी।

मौजूदा स्टॉक के बोझ को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल के 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं के स्टॉक में से लगभग 8.71 लाख मीट्रिक टन स्टॉक पहले ही राज्य में सीएपी या खुली स्टोरेज में पड़ा है, जिससे वैज्ञानिक तरीके से भंडारण क्षमता की कमी हो गई है और लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं को कम अनुकूल परिस्थितियों में स्टोर करना पड़ेगा। अनाज की धीमी उठाई का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार लगातार गेहूं और चावल की राज्य से उठाई की मांग करती रही है ताकि चावल की खरीद और स्टोरेज के लिए जरूरी भंडारण क्षमता बनाई जा सके। हालांकि पिछले कई महीनों से राज्य से गेहूं और चावल की औसत उठाई प्रति माह केवल 5 लाख मीट्रिक टन रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की उठाई की जाए या वैकल्पिक रूप से, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान आम लोगों को पेश मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अनाज का वितरण बढ़ाने जैसे प्रबंध किए जाएं, जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इससे रबी मंडीकरण सीजन 2026-27 के दौरान सुचारू खरीद कार्य सुनिश्चित होंगे और खरीफ मंडीकरण सीजन 2025-26 के लिए धान की मिलिंग को तेज किया जा सकेगा। एक अन्य मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खरीद के लिए फंडों का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह द्वारा किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय स्टेट बैंक जो ब्याज दर वसूल रहा है, वह भारतीय खाद्य निगम पर लागू रिकवरी दर से 0.5 प्रतिशत अधिक है और मासिक मिश्रित आधार पर ब्याज लगा रहा है।

बंगाल में सरकार बनती है तो प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा : अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री ने बंगाल के अंतिम दो चरणों के चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया

एजेंसी (हि.स.)

कोलकाता

पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में घुसपैठ पर सख्ती, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा गया है।

घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यदि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठ के मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो (डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट) की नीति के तहत प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और मवेशी तस्करी पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई।

राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी रिक्त सरकारी पदों को केवल योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। नकद के बदले नौकरी जैसी अनियमितताओं को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने स्थायी नौकरियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही।

युवाओं के लिए घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट देने की भी घोषणा की गई है। आर्थिक विकास के संदर्भ में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भूमि नीति में बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की बात कही।

उन्होंने बताया कि राज्य में चार नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनके स्थान बाद में तय किए जाएंगे। पूर्व मेदिनीपुर जिले में हल्दिया बंदरगाह के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। साथ ही ताजपुर और कुलपी में गहरे समुद्री बंदरगाह विकसित करने की योजना है। चाय और जूट उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा पश्चिम बंगाल को ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला सशक्तिकरण को लेकर घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त परिवहन की सुविधा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विशेष समिति से कराने की बात कही गई है।

घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। प्रत्येक मंडल में महिला थाने और हर पुलिस जिले में महिला डेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए दिन और रात दोनों समय सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।

परिसीमन का मुद्दा गंभीर, महिला आरक्षण की आड़ में सरकार कर रही जल्दबाजी : कांग्रेस

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की शुक्रवार को बैठक हुई। इसका उद्देश्य संसद के आगामी तीन दिवसीय अधिवेशन के लिए पार्टी की रणनीति बनाना था। बैठक में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने विधायिका में महिलाओं के आरक्षण के साथ होने जा रहे परिसीमन को गंभीर मुद्दा बताते हुए सर्वसम्मिति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र की राजग सरकार राजनीति से प्रेरित होकर विधानसभा चुनावों के बीच में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक लाने जा रही है।

सीडब्ल्यूसी की बैठक आज पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सदस्य शामिल हुए। पत्रकार वार्ता में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में संसद का विशेष सत्र और पश्चिम एशिया से जुड़ा संघर्ष दो मुद्दे थे। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे ने 16 से 30 मार्च के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को तीन पत्र लिखे।

इनमें से एक पत्र विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ लिखा गया था। हमारी मांग थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इसमें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो और विपक्ष को सरकार की मंशा बताई जाए। इस मुद्दे पर आम सहमति बनने का प्रयास किया जाए।

समिति की बैठक में खरगे ने अपने शुरूआती वक्तव्य में सरकार के फैसले पर गंभीर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर सरकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले जल्द से जल्द संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है। विपक्ष की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हम चाहते थे कि सरकार 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए मतदान के आखिरी दिन के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर गंभीरता से चर्चा करे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को अभी तक सरकार की मंशा का पता नहीं है। विधायकों और प्रस्तावों पर कोई विशेष जानकारी नहीं है। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मोदी सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से 816 करने जा रही है, यानी 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके परिसीमन पर गंभीर परिणाम होंगे और इस पर बहुत गहरे विचार-विमर्श की जरूरत है।

खरगे ने महिला आरक्षण को लेकर संसद की बैठक को चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन बताया और कहा कि आयोग से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि वह इस विषय पर ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के बीच बैठक से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लगे अधिकांश सांसद अपने क्षेत्र में व्यस्त होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने साथ ही इस बात को दोहराया कि कांग्रेस सामाजिक न्याय की पक्षधर है। महिलाओं को पंचायत और निकायों में अधिकार दिलाने वाली कांग्रेस ही थी।

ज्ञान को धन में परिवर्तित करने को तकनीक के साथ कुशल कार्यबल, अनुसंधान भी जरूरी: गडकरी

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञान को धन में परिवर्तित के लिए नवाचार, विज्ञान तथा तकनीक के साथ-साथ कुशल कार्यबल और निरंतर अनुसंधान पर जोर देना आवश्यक है।

गडकरी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद की ओर से यहां आयोजित 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार और प्रदर्शनी 'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा ,वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता से समझौता न करना और शॉर्टकट से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि तत्काल निर्णय लिए जाएं, परियोजना योजना अच्छी हो और काम की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अगर हम नई तकनीक अपनाएं और काम करने के तरीके को सुधारें तो परियोजनाओं की लागत काफी कम हो सकती है। इसके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और जरूरी मंजूरियों को पहले ही निपटाया जाए क्योंकि पहले की देरी और प्रशासनिक बाधाओं ने प्रोजेक्ट की समयसीमा और ठेकेदारों के बजट को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में केवल कम लागत ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और प्रदर्शन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना चाहिए। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी बल्कि खर्च भी घटेगा। साथ ही सड़क बनाने में प्लास्टिक कचरे और पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय अवसंरचना कंपनियों ने दुबई, कतर और कई अफ्रीकी देशों में प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। गडकरी ने समारोह में विजेताओं को 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए और निर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्र में गुणवत्ता एवं नवाचार में उनके योगदान के लिए उन्हें बधाई दी।

वृंदावन में लुधियाना के श्रद्धालुओं की नाव यमुना में पलटी, 10 की मौत

एजेंसी (हि.स.)

मथुरा

लुधियाना पंजाब से वृंदावन आए 30 श्रद्धालुओं से भरी नाव पंटून पुल से टकराकर यमुना नदी में पलट गई। इस हादसे में दस श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से 15 लोगों को बचा लिया है। इनमें से एक श्रद्धालु को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है।

बताया गया कि 150 लोगों का दल लुधियाना, पंजाब और मुक्तेश्वर से वृंदावन आया था। शुक्रवार लगभग तीन बजे यह लोग नाव में बैठकर यमुना नदी में सैर कर रहे थे। तभी केसी घाट पर इन्हीं श्रद्धालुओं की एक नाव पंटून पुल से टकराकर यमुना नदी में पलट गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। पुलिस और गोताखोरों ने नदी में डूबे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। नाव पनटने की सूचना मिलते ही दुर्घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिससे बचाव कार्य में थोड़ी बाधा आई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की खबर पर डीएम, एसएसपी और डीआईजी ने मौके पर जायजा लिया और गंभीर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

मथुरा डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने वृंदावन नाव हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि कते हुए बताया कि पांटून पुल से टकराने के कारण नाव के पलटने की सूचना है। इस मामले में नाव में सवार लोगों की सही संख्या की जानकारी ली जा रही है। इसके लिए नाव में सवार लोगों से बातचीत की जा रही है। 25 से 27 लोगों के नाव में सवार होने की बात कही जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

फसल खरीद को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे कांग्रेसी नेता: नायब सिंह सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल फसल खरीद को लेकर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके अपने शासनकाल की बदहाल व्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं हैं। वर्तमान सरकार ने मंडियों में सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रत्येक मंडी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री, विधायक व प्रशासनिक अधिकारी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि 10 साल हरियाणा में कांग्रेस का शासन रहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने शासन नहीं किया बल्कि राज किया। उनके राज में किसानों को क्या-क्या परेशानियां होती थी। उस दौरान किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए 3 से 7 दिन तक मंडियों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। बोरियों की सप्लाई भी नहीं होती थी। मंडी में पड़ी फसल भी बारिश में भिगती थी, तो किसान अपने पैसे से तिरपाल लेकर आता था। कांग्रेस बताए कि उन्होंने अपने 10 साल में फसल सुरक्षा के लिए कितने गोदाम बनाए हैं। कांग्रेस के समय में फसल के अंदर कटौती होती थी। इनके समय में सिस्टम बहुत धीमा था। किसानों को पैसा भी समय पर नहीं मिलता था। यहां तक कि इनके समय में ये मुआवजे के भी 2-2 रुपये के चैक किसानों को देते थे और किसान का मजाक बनाते थे। आज हमारी सरकार उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदने का काम सरकार करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां देश के लिए ठीक नहीं थी, बल्कि उनके परिवार के लिए ठीक थी। इनकी गलत नीतियों के कारण इन्होंने देश को पीछे धकेला। कांग्रेस के आज हालात ऐसे हो गए हैं, जैसे पानी के बाहर मछली को रख दिया हो। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यदि गरीब की चिंता किसी ने की है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। उनकी सोच थी कि गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और जो व्यक्ति किसी कारण से भी सरकारी कार्यालयों में नहीं जा सकते, उन तक भी योजनाओं को पहुंचाया जाए। इसके लिए विकसित भारत यात्रा हर गांव और हर घर तक पहुंची है, जिससे हर गरीब व्यक्ति मजबूत और सशक्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने फसल खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गत 28 मार्च से सरसों की खरीद जारी है। अब तक मंडियों में 16 हजार 46 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है। इसमें से 3 हजार 421 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। शेष सरसों निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है। मंडियों से 1 हजार 558 मीट्रिक टन सरसों का उठान करवाया जा चुका है। किसानों को 6 हजार 200 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से अब तक 4 करोड़ 94 लाख रुपये का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार, गत 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी जारी है। अब तक मंडियों में 17 लाख 37 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। इसमें से 3 लाख 92 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अब बारिश रूकने के बाद उठान प्रकिया में तेजी आ जाएगी। किसानों को 2 हजार 585 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से अब तक 13 करोड़ 9 लाख रुपये का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। गत 6, 7 व 8 अप्रैल को बारिश के कारण प्रदेश के 4 जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा व कुरूक्षेत्र के कुछ गांवों में फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने स्वयं संबंधित जिलों के उपायुक्तों से बात कर स्थिति का पता लगाया है। फसलों को हुए नुकसान एवं भरपाई के लिए हिसार, सिरसा व फतेहाबाद के लिए पोर्टल खोल दिया गया था, बाकी नुक्सान वाले जिलों में भी तुरंत कारवाई कर ली जायेगी। अब तक इस पोर्टल पर तीनों जिलों के गांवों के 1 हजार 350 किसानों ने 10 हजार 88 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इनमें फतेहाबाद जिले के 9 गांव, हिसार के 10 गांव तथा सिरसा के 2 गांव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 8 अप्रैल को प्रदेश के मजदूरों के मिनिमम रेट्स में वृद्धि की है। अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11,275 रुपये से बढ़कर 15,220 तथा अर्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 12,430 रुपये से बढ़कर 16,780 रुपये हो गया है। इसी प्रकार, कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 13,704 रुपये से बढ़कर 18,500 रुपये और हाई स्किल्ड श्रमिकों का मासिक वेतन 14,389 रुपये से बढ़कर 19,425 रुपये हो गया है। श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। बैंक के मामले में जांच जारी है और यह मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कृषि विभाग के महानिदेशक राजनारायण कौशिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ प्रियंका सोनी आदि मौजूद रहे।

देहरा के ढलियारा में सड़क हादसे में पंजाब के तीन श्रद्धालुओं की मौत, 13 घायल

कपूरथला से आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढलियारा में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब कपूरथला (पंजाब) से आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

जानकारी के अनुसार हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस तकनीकी कारणों की जांच कर रही है। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। उक्त वाहन में कुल 35 व्यक्ति सवार थे, जो मूलतः पंजाब राज्य के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के बाद ज्वालामुखी मंदिर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वाहन ढलियारा के खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर-ट्राली सीधे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को खाई से बाहर निकाला। वहीं पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस और राहत दल भी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल देहरा में पहुंचाया गया।

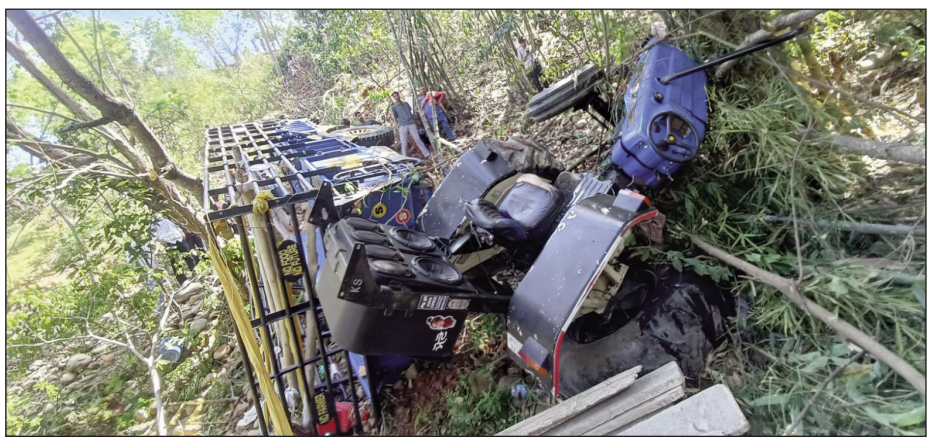

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस दल द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल देहरा पंहुचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा 3 व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया तथा 13 घायल लोगों का उपचार जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को आगे के उपचार हेतु डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा रेफर किया गया है। सवार व्यक्तियों में से 9 बच्चे व अन्य सवार पूरी तरह सुरक्षित हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा मृतकों एवं घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस थाना देहरा में भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं तथा दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच कज जा रही है।

उधर एसपी देहरा ने आम जनता एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय ओवरलोडिंग से बचे। निर्धारित गति सीमा का पालन करें, विशेषकर पहाड़ी एवं घुमावदार मार्गों पर सावधानी बरतें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट/हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा यात्रा से पूर्व वाहन की तकनीकी जांच सुनिश्चित करें।

आपदा सुरक्षा के लिए 118 करोड़ रुपये की पांच योजनाएं प्रस्तावित

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला जिले में आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए करीब 118 करोड़ रुपये के पांच प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों को राज्य आपदा न्यूनीकरण फंड के तहत मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष बैठक में लिया गया।

बैठक में जिले के अलग-अलग आपदा प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें रामपुर के वार्ड नंबर-1 में कल्याणपुर नाले के चैनलाइजेशन के लिए लगभग 3 करोड़ 21 लाख 34 हजार रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। इसके अलावा सुन्नी-शिमला मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 9 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है। चौपाल के सैंज क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित सड़क के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं चौपाल के खागना सड़क क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित हिस्से के सुधार के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपये की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही शिमला शहर के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से अलग-अलग सुरक्षा और सुधार कार्य करवाने का प्रस्ताव भी शामिल है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इन सभी प्रस्तावों को राज्य आपदा न्यूनीकरण फंड से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। जिन स्थानों पर भविष्य में खतरे की आशंका बनी रहती है, वहां स्थायी समाधान के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य आपदा न्यूनीकरण फंड का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और पहले से तैयारी को मजबूत बनाना है। इस फंड के माध्यम से भूस्खलन रोकने के उपाय, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, नदियों के किनारे सुरक्षा कार्य और सुरक्षित ढांचागत निर्माण जैसे काम किए जाते हैं। इसके साथ-साथ लोगों को जागरूक करने और आपदा के समय सही प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉक ड्रिल भी आयोजित किए जाते हैं।

निकाय चुनावों को लेकर भाजपा फैला रही भ्रम : कांग्रेस

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि भाजपा नगर निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में संभावित हार को देखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव 31 मई से पहले करवा दिए जाएंगे।

विनय कुमार ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा रोस्टर को लेकर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव रोस्टर में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और इसमें सभी वर्गों, जातियों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी चुनावों को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सफल नहीं होगी। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का सम्मान किया है और लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि होता है। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा को हर मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की आदत है, लेकिन अब यह ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और अब प्रदेश के हितों से भी किनारा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा का असली चेहरा देख चुकी है और अब उसके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है।

कई अभियानों के दौरान पांच नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त

अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने एक बड़ा नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जिसमें कई अभियानों के दौरान पांच नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि एक विशिष्ट सूचना के आधार पर माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद नैना गुंड बाबा खलील, संगम निवासी मोहम्मद जब्बार डार के पुत्र फैयाज अहमद डार के आवासीय घर पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान 3 किलो 99 ग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद किया गया। आरोपी फैयाज अहमद डार और उसके बेटे अरबाज अहमद डार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 82/2026 दर्ज की गई है और जांच जारी है। एक अन्य अभियान में पुलिस पोस्ट संगम की पुलिस टीम ने नैबस्ती मरहामा में नाका चेकिंग के दौरान एक हुंडई आई20 (जेके13जे-0803) को रोका। बाटागुंड त्राल निवासी शाहजादा सुवैद पुत्र मंजूर अहमद शाह और वारिस-उल-इस्लाम पुत्र नजीर अहमद शाह के पास से 488 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शिमला पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया चिट्टा सप्लायर, अंतर-राज्यीय नेटवर्क का खुलासा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला जिले के ठियोग थाना क्षेत्र में चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मादक पदार्थ की खेप के सप्लायर को पंजाब के मानसा जिले से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान शिवदेव सिंह (30) निवासी गांव बछौंआ, जिला मानसा (पंजाब) के रूप में हुई है। शिमला पुलिस की स्पेशल टीम उसे गिरफ्तार कर ठियोग ले आई है, जहां उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस के अनुसार यह गिरफ्तारी 1 अप्रैल को ठियोग थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान की गई है। मामले की जांच में तकनीकी विश्लेषण, पूछताछ और बैकवर्ड लिंक की पड़ताल के आधार पर सप्लायर तक पहुंच बनाई गई। दरअसल, 1 अप्रैल को ठियोग पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि मतियाना क्षेत्र में एक बोलेरो कैंपर में कुछ लोग मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त में शामिल हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वाहन को ट्रेस कर लिया। वाहन में सवार चार युवकों की पहचान चांद प्रकाश (32) निवासी निरमंड जिला कुल्लू, विजय कुमार (23) निवासी निरमंड जिला कुल्लू, अभिषेक (24) निवासी ननखड़ी जिला शिमला और कैलाश (26) निवासी निरमंड जिला कुल्लू के रूप में हुई। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली, जिसमें 34.440 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया। इसके बाद चारों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

संक्षिप्त-समाचार

महर्षि मार्कण्डेश्वर महादेव मंदिर में 13 अप्रैल से बैसाखी मेला

नाहन। सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत बनकला में इस वर्ष भी बैसाखी का पावन पर्व बड़े धूमधाम और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत बनकला के ऐतिहासिक महर्षि मार्कण्डेश्वर महादेव ढिमकी मंदिर में आयोजित होने वाला यह तीन दिवसीय बैसाखी मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और खेल प्रतिभाओं को भी एक बड़ा मंच प्रदान करता है। मेले का विधिवत शुभारंभ 13 अप्रैल, सोमवार को सुबह 9:00 बजे एक भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। यह यात्रा बोहलियों मंदिर से शुरू होकर ढिमकी स्थित महर्षि मार्कण्डेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इसी दिन शाम को मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहाँ भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेले का मुख्य आकर्षण 14 अप्रैल, मंगलवार को रहेगा। दिन की शुरुआत सुबह 7:00 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन से होगी, जिसके बाद 10:00 बजे झंडा पूजन की रस्म अदा की जाएगी। दोपहर 12:00 बजे से आम जनता के लिए विशेष भंडारा शुरू होगा। दोपहर बाद 4:00 बजे से उत्तर भारत की प्रसिद्ध ह्यदंगल(कुश्ती) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस दंगल में हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के नामी पहलवान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। शाम को संध्या आरती के बाद रात्रि 8:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसका मूल मंत्र हर प्रतिभा को मंचरखा गया है, ताकि स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिल सके।

उपमुख्यमंत्री चौधरी को खनन निदेशालय में काम करते मिले निलंबित अधिकारी, जांच के आदेश

जम्मू। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि गंभीर आरोपों पर निलंबित या स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को खनन निदेशालय कार्यालय में अभी भी काम करते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच शुरू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे द्वारा निलंबित किए गए अधिकारी अभी भी जम्मू स्थित खनन निदेशालय कार्यालय में काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को गंभीर आरोपों पर या तो निलंबित किया गया था या कश्मीर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन मैंने उन्हें यहां काम करते हुए पाया। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनके दौरे के दौरान निदेशक और संयुक्त निदेशक दोनों कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है। मैं सचिवालय जाकर इस मामले को उठाऊंगा। अवैध खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए चौधरी ने कहा कि मैं मानता हूं कि कुछ अधिकारियों के कारण अवैध खनन हो रहा है और विभाग में कुछ कमियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी गतिविधियों को आंतरिक रूप से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जम्मू स्थित खनन निदेशक कार्यालय से अवैध खनन को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज और ऐसे अधिकारियों की मौजूदगी की जांच का आदेश दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना

श्रीनगर। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने आने वाले दिनों में पूरे जम्मू और कश्मीर में मौसम का मिजाज काफी हद तक स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही छिटपुट स्थानों पर रुक-रुक कर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 10 अप्रैल आमतौर पर शुष्क रहेगा, हालांकि दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 11 अप्रैल को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है दोपहर और शाम के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 12 अप्रैल को ज्यादातर शुष्क रहने का अनुमान है अलग-अलग इलाकों में दोपहर के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। 13 और 14 अप्रैल को लंबे समय तक शुष्क रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मौसम स्थिर रहेगा। 15 अप्रैल को मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रहेगी, दोपहर में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। हालाँकि 16 और 17 अप्रैल के बीच बदलाव की उम्मीद है जब आम तौर पर बादल छाए रहने से छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, खासकर दोपहर और शाम के समय। 18 से 20 अप्रैल तक मौसम फिर से स्थिर होने की उम्मीद है जिससे पूरे क्षेत्र में मुख्यतः शुष्क स्थिति बनी रहेगी।

कठुआ में जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा

कठुआ। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने आगामी जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के सुचारु संचालन को लेकर जिला कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 19 अप्रैल 2026 को होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त ने पेयजल, बिजली आपूर्ति, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। साथ ही जेकेएसएसबी के निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस विभाग को सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, उचित चेकिंग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए गए।

नादौन की जनता का विशेष ध्यान रखते हैं सीएम : कमलेश ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं और सराहनीय योजनाएं आरंभ की हैं। वह नादौन विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके की जनता की समस्याओं और जरुरतों से वाकिफ हैं तथा इस क्षेत्र की जनता को सर्वोपरि मानते हुए यहां के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करने के साथ-साथ आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

शुक्रवार को गांव सेरा के विश्राम गृह में जनसमस्या निवारण एवं राहत राशि वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कमलेश ठाकुर ने कहा कि आज नादौन क्षेत्र का नाम देश-विदेश में प्रसिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति नादौन क्षेत्र की जनता के स्नेह और सहयोग से ही यह संभव हो रहा है। कमलेश ठाकुर ने बताया कि क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष व्यवस्था की है और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप भी बनाए हैं। किसी भी जनसमस्या का पता चलने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। कमलेश ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विशेषकर बूथ प्रभारियों से कहा कि अगर उनके क्षेत्र के किसी व्यक्ति को कोई समस्या है या किसी अनहोनी घटना के कारण उसको तुरंत मदद की आवश्यकता है तो तुरंत इसकी सूचना दें, ताकि प्रभावित व्यक्ति की तत्काल मदद की जा सके। इस अवसर पर कमलेश ठाकुर ने लगभग 140 जरुरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 39 लाख रुपये की राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।

कठुआ पुलिस ने कई स्थानों पर थाना दिवस आयोजित कर सुनीं जन समस्याएं

कठुआ। पुलिस-जन संबंधों को मजबूत करने और लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में थाना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लक्ष्मणपुर (मंजली), कठुआ (घाट्टी), हीरानगर (शेरपुर), बिलावर, बसोहली (भूंड), मल्हार और बनी (रौलका) सहित कई थाना क्षेत्रों में आयोजित किया गया जहां जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ खुलकर बातचीत की। इस दौरान किरायेदार सत्यापन, नशा तस्करी, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में जागरूक करते हुए अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा जबकि अन्य समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा।

एचआरटीसी पेंशनरों ने उठाई मेडिकल बिल भुगतान की मांग, जल्द समाधान की उम्मीद

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों की एक बैठक शुक्रवार को नाहन में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2016 से लंबित एरियर के भुगतान, पिछले तीन वर्षों से मेडिकल बिलों की अदायगी न होने तथा पेंशन के नियमित रूप से न मिलने जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

पेंशनर संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियां बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन तीन वर्षों से मेडिकल बिलों का भुगतान न होने के कारण पेंशनरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की प्रमुख मांग है कि लंबित मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान किया जाए और 2016 से बकाया एरियर जल्द जारी किए जाएं।

ठाकुर ने जानकारी दी कि 30 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनरों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। हालांकि, इस संबंध में अभी तक राज्य स्तर पर कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

एनडीपीएस मामलों की समीक्षा बैठक में एसएसपी कठुआ सख्त, गुणवत्तापूर्ण जांच व त्वरित निस्तारण पर जोर

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने जिला पुलिस कार्यालय कठुआ में वर्ष 2025-26 के एनडीपीएस मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

बैठक के दौरान एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तारी, बरामदगी, जमानत/दोषसिद्धि दर, लंबित जांच, सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता, संपत्ति कुर्की, बैंक खाते फ्रीज, पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई, ड्रग हॉटस्पॉट विजिट, जागरूकता अभियान व सीसीटीवी जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। एसएसपी ने जांच अधिकारियों के प्रदर्शन और मामलों के निस्तारण की गति पर भी ध्यान देते हुए निर्देश दिए कि एनडीपीएस मामलों की जांच तेज की जाए, समय पर चार्जशीट दाखिल हो और दोषसिद्धि दर में सुधार लाया जाए। उन्होंने सक्रिय पुलिसिंग, गश्त बढ़ाने, खुफिया तंत्र मजबूत करने और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

बयान

फारूक अब्दुल्ला ने तनाव कम होने पर जताई खुशी

युद्ध विनाश लाता है, संवाद ही समाधान: पूर्व मुख्यमंत्री

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और संघर्ष विराम की दिशा में बढ़ते कदमों का स्वागत किया है। डॉ. अब्दुल्ला ने इसे मानवता की जीत बताते हुए कहा कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह शांति स्थायी साबित होगी।

डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पश्चिम एशिया में हालिया तनाव में आई कमी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान जैसे देश मेज पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, वह पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संकेत है। अब्दुल्ला ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि दोनों देशों को यह सद्बुद्धि मिली कि वे मेज पर बैठकर बात करें। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है; यह केवल तबाही और बबार्दी लाता है। संवाद ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे जटिल से जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक दुनिया में एक क्षेत्र में होने वाला संघर्ष केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करता है। फारूक अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम की आवश्यकता को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया दुनिया के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि वहां युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है, जिससे भारत जैसे देशों में महंगाई बेकाबू हो सकती है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के उन लाखों लोगों का जिक्र किया जो खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। अब्दुल्ला ने कहाः हमारे हजारों नौजवान और कामगार उन क्षेत्रों में काम करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं। युद्ध के कारण उनकी जान और आजीविका दोनों पर खतरा मंडरा रहा था। आर्थिक स्थिरताः उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तनाव कम नहीं होता, तो दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती थी, जिसका सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ता। अब्दुल्ला ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में होने वाली बाधाओं पर भी चिंता जताई थी, जो अब शांति की स्थिति में सुचारू रूप से चल सकेंगे। डॉ. अब्दुल्ला ने भारत सरकार से अपील की कि वह इस शांति प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भारत के संबंध अमेरिका और खाड़ी देशों, दोनों के साथ बेहतर हैं, ऐसे में भारत एक कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के ऐतिहासिक स्टैंड का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को अपनी न्यायसंगत विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हो रही चर्चाओं के बजाय मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, शांति का असली पुरस्कार उन निर्दोष लोगों की जान बचाना है जो युद्ध की विभीषिका में पिसते हैं। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय पश्चिम एशिया में फिर से स्थिरता बहाल करने की कोशिश कर रहा है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्योन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

भारत 1.20 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ विकास की नई शक्ति का प्रतीक: घोष

हरियाणा के राज्यपाल ने टाईकॉन चंडीगढ़-2026 की दो दिवसीय कान्फ्रेंस का किया शुभारंभ

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि आज भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार-आधारित विकास की शक्ति का प्रमाण है जिसमें 1 लाख 20 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं जिनसे 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने यह बात आज चंडीगढ़ स्थित हयात रिजेंसी में टाईकॉन चंडीगढ़-2026 की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थितगण को संबोधित करते हुए कही। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कॉन्फ्रेंस की सराहना करते हुए उन्होंने आयोजकों को बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को रोजगार मांगने की नहीं बल्कि रोजगार देने की सोच के साथ नवाचार की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करके हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप विकसित भारत बनाने के यज्ञ में अपनी आहुति डाल सकते हैं।

राज्यपाल प्रो. घोष ने कहा कि भारत देश में विशाल मध्यम वर्ग है जिनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर यदि आधुनिक तकनीक के साथ नए प्रयोग किए जाएं तो युवा वर्ग के सामने रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि देश में खाद्य प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में नवीन प्रयोग करने की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि देश में इसके लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्यपाल प्रो. घोष ने कहा कि यह खुशी और गर्व की बात है कि हरियाणा राज्य 7000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ एक महत्वपूर्ण योगदान कर्ता के रूप में उभरा है। उन्होंने हरियाणा की स्टार्टअप नीति की सराहना करते हुए इसे उद्यमियों के अनुकूल बताया।

प्रो. घोष ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम ने खुद को एक वैश्विक स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि टाईकॉन चंडीगढ़ उत्तर भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह बहुत उत्साहजनक है कि पंचकूला एक उभरते हुए विकास केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। अपनी सुनियोजित अवसंरचना, रणनीतिक कनेक्टिविटी और चंडीगढ़ के निकट होने के कारण, पंचकूला अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स, आईटी कंपनियों और नवाचार-आधारित निवेश को आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि टाई चंडीगढ़ 23 देशों में फैले 67 से अधिक चैप्टर्स वाले वैश्विक टाई नेटवर्क का हिस्सा है और यह सबसे सक्रिय और प्रभावशाली इकाइयों में से एक है। 450 से अधिक चार्टर सदस्यों और उद्यमियों के मजबूत समुदाय के साथ, इसने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया है। इसके प्रमुख कार्यक्रम, टाई वुमैन, टाई यूनिवर्सिटी और टाई यंग एंटरप्रोन्योर सभी स्तरों पर प्रतिभा को विकसित कर रहे हैं जो हर वर्ष 300 से अधिक प्रतिभागियों को जोड़ते हुए भविष्य के उद्यमियों की मजबूत आधारशिला तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने खुशी जताई कि टाई चंडीगढ़-2026 में 2000 से अधिक प्रतिनिधि, 50 से अधिक निवेशक, 80 से अधिक वक्ता और 50 से अधिक स्टार्टअप्स शामिल हैं, उन्होंने इसे पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और ऊर्जा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सहयोग, नवाचार और समावेशन के माध्यम से इस पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत बनाते रहें।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष, टाई चंडीगढ़ के अध्यक्ष पुनीत वर्मा, पूर्व अध्यक्ष मुरली बुक्कापटनम, ब्रह्म अलरेजा, रवि शर्मा, विशाल केडिया, सुमेध सचदेव, आशु शर्मा, ऋतिका सिंह, पूजा नायर, जेबी सिंह, अजय तिवारी, हिरदेश मदान, सतीश के. अरोड़ा व हरित मोहन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पेयजल सप्लाई के लिए की जाएगी गुरूग्राम वाटर सप्लाई चैनल की रिमोडलिंग: नायब सिंह सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में पेयजल सप्लाई के लिए बनाए जा रहे गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल का कार्य तेज गति से पूरा किया जाए ताकि लोगों को निश्चित समय में पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को रिमोडेलिंग ऑफ गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल की स्टेंडिंग फाईनेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत के काकरोई हैड से बसई जल घर तक बनने वाले इस चैनल से गुरुग्राम को 686 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो आगामी 2050 तक की आबादी को पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो सकेगा। लगभग 70 किलोमीटर लम्बाई के इस चैनल के निर्माण पर लगभग 1993 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इस कार्य में पूर्ण रूप से अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाईन बिछाई जाएगी ताकि पानी की शुद्धता को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इस सप्लाई चैनल की क्षमता को बढ़ाकर एक हजार क्यूसिक की जाए ताकि इसका लाभ और अधिक आबादी को अधिक समय तक मिलता रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि गुरुग्राम को 500 क्यूसिक पानी सप्लाई एनसीआर कैनाल से किया जाएगा। इस प्रकार गुरुग्राम को आगामी वर्षों में 1500 क्यूसिक पानी की सप्लाई होगी। इसके अलावा मेवात क्षेत्र के लिए भी 389 क्यूसिक पेयजल का अलग से प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्य पारदर्शी ढंग से किया जाए और उच्च क्वालिटी का होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पेयजल सप्लाई प्रोजेक्ट का कार्य अढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसकी लगातार मोनिटरिंग की जाए और इस कार्य को लक्ष्य से लगभग तीन माह पहले पूरा कर लिया जाए। गुरुग्राम की आबादी लगातार बढ़ रही है और अब गुरुग्राम महाग्राम बन गया है। इसकी पूरी आबादी को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाना हरियाणा सरकार का दायित्व एवं जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अण्डर ग्राउण्ड बिछाई जाने वाली इस पेयजल पाईप लाईन पर सोलर पैनल लगाने का भी प्रावधान किया जाए ताकि सौर ऊर्जा से बिजली सुलभ हो सके। इसके अलावा गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल से मिलने वाले पानी का उचित डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने के लिए वाटर ट्रिटमेंट प्लांट बनाने के लिए भी जगह का चयन कर लिया जाए ताकि उन पर जल्द कार्य शुरू करवाया जा सके।

मुख्यमंत्री अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रणाली शुरू करेंगे

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार अगले महीने एक स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली शुरू करने जा रही है, जो कागजरहित और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह पहल मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में की जा रही है। इस सुधार अभियान का नेतृत्व करते हुए वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डॉ. सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य की राजस्व व्यवस्था में तेजी, जवाबदेही और तकनीक के माध्यम से व्यापक बदलाव पर जोर दिया गया।

डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि लगभग 1,900 नव-प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष पटवारियों को जल्द से जल्द जिलों में तैनात किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये डिजिटल रूप से सक्षम

1,900 पटवारियों की जल्द होगी नियुक्ति

अधिकारी नई राजस्व प्रणाली की रीढ़ बनेंगे और तकनीकी ढांचे को मजबूत करेंगे। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों को तुरंत निपटाया जाए और पांच दिन से अधिक की देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं।

फिल्ड स्तर पर ये 1,900 तकनीकी पटवारी भूमि प्रशासन से जुड़े अहम कार्यों को संभालेंगे, जैसे भूमि रिकॉर्ड का आधार से लिंक करना, लाल डोरा नक्शों का अपडेट, रोवर तकनीक से भूमि का सटीक सीमांकन, एग्रीस्टैक के तहत डिजिटल डेटा का सत्यापन और कब्जे से जुड़े खसरा-खाना कष्ट मामलों का त्वरित निपटान आदि।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कुरुक्षेत्र: थ्रू द एजेस के दूसरे दिन क्लासिकल कूल बैंड की सांस्कृतिक संध्या ने बांधा समां

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कुरुक्षेत्र: थ्रू द एजेस के दूसरे दिन शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन केंद्र, स्वदेशी शोध संस्थान, जीओ गीता तथा विजन कुरुक्षेत्र के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में देश-विदेश से आए विद्वान कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों पर अपने विचार साझा कर रहे हैं।

सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या में क्लासिकल कूल बैंड की संयोजिका प्रभजोत और उनकी टीम ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। बैंड के 11 छात्र-छात्राओं ने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, देशभक्ति गीत, सूफी गायन तथा नए-पुराने लोकप्रिय गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत कर सभागार में सांस्कृतिक समा बांध दिया। कलाकारों ने अपनी सधी हुई गायकी, भावपूर्ण नृत्य और संगीत के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक परंपराओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। देशभक्ति गीतों और सूफी गायन की प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में शास्त्रीयता और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित श्रोताओं को देर तक बांधे रखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने न केवल सम्मेलन के शैक्षणिक वातावरण को जीवंत बनाया बल्कि भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को भी प्रभावी ढंग से सामने रखा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने कलाकारों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को समृद्ध बनाते हैं तथा युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र: थ्रू द एजेस जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भारतीय इतिहास और संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम बनती हैं।

कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. आबिद अली और रितु ने प्रभावशाली ढंग से किया और विभिन्न प्रस्तुतियों का सुंदर परिचय देते हुए कार्यक्रम को रोचक बनाए रखा।

इस अवसर पर प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा, विजन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा, प्रो. आर.के. देसवाल, प्रो. भगत सिंह, प्रो. अमित लुदरी, डॉ. सरिता आर्य, डॉ. रामचंद्र, डॉ. सी.डी.एस. कौशल, दर्शन कुमार, संजीव कुमार, रणदीप तथा सहित अनेक शिक्षाविद, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कुरुक्षेत्र में पहली बार सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर मनाया जाएगा बैसाखी महोत्सव 2026: विश्राम कुमार मीणा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र सिख गुरुओं की पावन धरा पर प्रदेश सरकार की तरफ से बैसाखी महोत्सव 2026 का बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन 13 व 14 अप्रैल को केडीबी मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस बैसाखी महोत्सव में देश की परंपरागत सांस्कृतिक विरासत के झरोखे देखने को मिलेंगे।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैसाखी महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 13 अप्रैल को राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण भी शिरकत करेंगे। इस दो दिवसीय महोत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र ड्रोन शो रहेगा। इस ड्रोन शो के लिए एक निजी एजेंसी को हायर किया गया है। यह एजेंसी ड्रोन शो के लिए लगभग 500 ड्रोन का प्रयोग करेंगे और आकाश में रंग बिरंगी लाइटों से बैसाखी महोत्सव के अहम लम्हों को दिखाने का अनोखा प्रयास किया जाएगा। इस पावन धरा पर पहली बार जहां बड़े स्तर पर बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पहली बार ही कुरुक्षेत्र में ड्रोन शो देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए कुरुक्षेत्र ही नहीं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आमंत्रित किया जा रहा है।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि 14 अप्रैल को होने वाले ड्रोन शो का दृश्य कार्यक्रम के साथ-साथ आस पास के क्षेत्र के लोग भी देख पाएंगे। इस वैशाखी महोत्सव में स्कूलों, कॉलेजों के कलाकारों के साथ-साथ हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की तरफ से भी बेहतरीन कार्यक्रमों की प्रस्तुति रहेगी।

इस मौके पर एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अमन कुमार, नगराधीश आशीष कुमार, डीएसपी सुनील कुमार, डीआरओ चेतना चौधरी, डीडीपीओ विकास कुमार आदि उपस्थित थे।

शिक्षा चिकित्सा की अलख जगाकर आमजन तक सुविधाओं को पहुंचाया संत बाबा मान सिंह ने: नवीन जिंदल

सिटी दर्पण संवाददाता
पिहोवा

गुरुद्वारा सचखंड ईशर दरबार जुरासी में ब्रह्मलीन संत बाबा मान सिंह की स्मृति में तीन दिवसीय बरसी समागम गुरुवार को संपन्न हुआ। इस समागम में हजारों की संख्या में दूर दराज से पहुंची और संगत ने संत बाबा मान सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद संत महात्माओं के विचारों को सुना। संत समागम में पहुंचे सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि सांसारिक सुखों का त्याग कर अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाने वाला व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। दिवंगत संत बाबा मान सिंह का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा।

सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि ऐसे लोग धरती पर ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं। संत बाबा मान सिंह ने अपना जीवन शिक्षा, चिकित्सा, कार सेवा जैसे जनहित के कार्यो में लगाया। संत बाबा मान सिंह जो राह दिखा कर गए वे उसका अनुसरण करके यहां के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सांसद जिंदल ने कहा कि जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई। संत बाबा मान सिंह ने हमेशा कार सेवा के जरिए लंगर लगाकर पीड़ितों की मदद की। इस क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए अकादमी की स्थापना, लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज, चैरिटेबल अस्पताल स्कूल आदि उनकी इस क्षेत्र को देन हैं।

उन्होंने कहा कि संत बाबा मान सिंह देश और समाज के प्रति सकारात्मक सोच के संत थे। इस समागम में संतो ने संगत को गुरबाणी से जोडकर निहाल किया। संत बाबा मणि सिंह ने कहा कि गुरबाणी मे जात पात ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होता। परमात्मा कभी किसी का कोई बुरा नहीं करते। आज जो कुछ भी हमारे पास है। वह सब कुछ परमात्मा की देन है। समागम में रागी ढाडी जत्थे, कथावाचकों द्वारा शब्द कीर्तन के जरिए संगत को गुरुचरणों से जोड़ा। इस समागम में भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी, बाबा दिलबाग सिंह, बाबा सुरजीत सिंह, निशान सिंह, राव वीरेंद्र सरपंच, मार्केट कमेटी चेयरमैन तरणदीप सिंह वड़ैच, महामंत्री विकास गर्ग, गुरिंदरजीत सिंह नत, सुरेश राणा बीबीपुर, जगत सिंह चंडीगढ़ फार्म, बलविंद्र सिंह काका, प्यारा सिंह, रामपाल, सतनाम सिंह व जसबीर जस्सी आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

हरियाणा में एक आईएएस व दो एचसीएस अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़। हरियाणा ने तत्काल प्रभाव से एक आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारी डॉ. सुभिता ढाका को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है। वहीं, एचसीएस अधिकारी सुश्री चिनार को स्कूल शिक्षा विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। श्री हरि राम को श्री अप्रतिम सिंह के स्थान पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक), हथीन नियुक्त किया गया है। श्री अप्रतिम सिंह के नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। वे अपना कार्यभार छोड़ने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

हरियाणा में 4 आईएएस व 13 एचसीएस अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़। हरियाणा ने तत्काल प्रभाव से 4 आईएएस और 13 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारी श्री विजय कुमार सिद्धप्पा भाविकट्टी, को राज्यपाल का सचिव, श्रम आयुक्त तथा श्रम विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। श्री अनीश यादव, जो वर्तमान में विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे, को हैफेड तथा हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन, गनौर के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। श्री विक्रम को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंध निदेशक तथा ऊर्जा विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है। वे हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक भी रहेंगे। ी सचिन गुप्ता, जो वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव तथा एचएसएमआईटीसी के प्रबंध निदेशक तथा रोहतक के उपायुक्त हैं, को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक के प्रशासक तथा शहरी सम्पदा, रोहतक अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है। एचसीएस अधिकारियों में श्री अमित कुमार-1 को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पुन्हाना लगाया गया है। श्री वीरेंद्र चौधरी को श्री शम्भू के स्थान पर जिला परिषद कुरुक्षेत्र तथा डीआरडीए कुरुक्षेत्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री मनीष कुमार लोहान, जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को खान एवं भूविज्ञान विभाग तथा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है। श्री सुरेंद्र सिंह-2 को मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां, सोनीपत में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) नियुक्त किया गया है। श्री वेद प्रकाश को उपमंडल अधिकारी (नागरिक) डबवाली; श्री भूपेंद्र सिंह को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पलवल तथा श्री अश्वीर सिंह को उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बरवाला लगाया गया है। श्री संजीव कुमार को श्री मनोज कुमार-1 के स्थान पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बावल नियुक्त किया गया है। सी प्रकार, एचसीएस अधिकारी सुश्री अनमोल को सहकारी चीनी मिल, सोनीपत का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। सुश्री ज्योति नागपाल को सिटी मजिस्ट्रेट गुरुग्राम; सुश्री सपना यादव को संयुक्त निदेशक (प्रशासन), हिपा गुरुग्राम; श्री हनी बंसल को उपमंडल अधिकारी (नागरिक) फरीदाबाद तथा श्री अंकित कुमार-2 को उपमंडल अधिकारी (नागरिक) गोहाना नियुक्त किया गया है। एचसीएस अधिकारी श्री शंभू तथा श्री मनोज कुमार-1 के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। दोनों अधिकारी कार्यमुक्त होने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

कविता से विकसित होती है संवेदनशीलता और सृजनात्मकता: प्रो. सुनीता सिरोहा

कुरुक्षेत्र। कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में साहित्यिक क्लब, अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के सेमिनार हॉल में अंतर-विभागीय काव्य-पाठ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि विकसित करना तथा सार्वजनिक वक्तृत्व और साहित्यिक अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो. सुनीता सिरोहा, डीन, कला एवं भाषा संकाय एवं आईसीसी की अध्यक्षा की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। डॉ. हरविंदर कौर, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कविता को भावनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बताया। इस अवसर पर प्रो. सुनीता सिरोहा ने अपने संबोधन में कहा कि कविता विद्यार्थियों में कल्पनाशक्ति, संवेदनशीलता और भाषाई सृजनात्मकता का विकास करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियाँ आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच और सांस्कृतिक समझ को सुदृढ़ बनाती हैं तथा मानवीय मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. ब्रजेश साहनी ने की। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के 09 विभागों से 30 प्रतिभागियों ने भाग लेकर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपनी कविताओं का प्रभावशाली पाठ प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों का मूल्यांकन निर्णायक मंडल–डॉ. विक्रम खर्ब, डॉ. रमेश एवं डॉ. प्रिया गौतम–द्वारा उच्चारण, अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और समग्र प्रस्तुति के आधार पर किया गया। प्रतियोगिता में बी.एससी. फिजिकल साइंस (चतुर्थ सेमेस्टर, आईआईएचएस) की छात्रा सुश्री परीक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1100 का नकद पुरस्कार जीता। एम.ए. अंग्रेजी की छात्रा कल्पना ने द्वितीय स्थान (700) तथा हुसनप्रीत कौर ने तृतीय स्थान (500) प्राप्त किया।

द्वितीय वार्षिक परीक्षा के आवेदन हेतु बढाई अंतिम तिथि बिना विलम्ब शुल्क 12 अप्रैल तक सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (नियमित) एवं गुरूकुल/विद्यापीठ (पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक/उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक) की दो बार परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढाकर 12 अप्रैल, 2026 कर दिया गया है। परीक्षार्थी बिना विलम्ब शुल्क के समय रहते आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 में प्रविष्ट हुए हैं लेकिन अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार का मौका दिया गया है।

देश–विदेश में तेजी से बढ़ रहा है होम्योपैथी का प्रसार : डा. मंजू शर्मा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कुरुक्षेत्र डॉ. मंजू शर्मा ने कहा कि होम्योपैथी का प्रसार देश-विदेश में तेजी से बढ़ रहा है तथा यह दिवस महान चिकित्सक डॉ. सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं एलोपैथी तीनों ही स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. मंजू शर्मा शुक्रवार को विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर आयुष विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा महानिदेशक आयुष हरियाणा के निदेर्शानुसार सेक्टर-3 स्थित शिव मंदिर परिसर में निःशुल्क होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर में बोल रही थी। इस शिविर में कुल 268 मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम की शुरूआत जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. मंजू शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने के साथ हुई। मंदिर कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह चौहान ने आयुष विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके उपरांत सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. भावना द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा होम्योपैथी एवं आयुर्वेद के महत्व पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए।

डॉ. रितु व डॉ. गुरप्रीत ने कहा कि कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं होती, सभी की अपनी सीमाएं होती हैं, किंतु समन्वित दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। योग विशेषज्ञ मनजीत ने कहा कि होम्योपैथी और योग का संयुक्त उपयोग रोगों के उपचार में अत्यंत प्रभावी है। अस्थमा रोगियों में होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर उपचार करती है, जबकि योग में प्राणायाम के माध्यम से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाई जाती है। इसी प्रकार जोड़ों के दर्द में होम्योपैथिक दवाओं के साथ योग की स्ट्रेचिंग तकनीकें लाभकारी सिद्ध होती हैं। डॉ. शुभम ने होम्योपैथिक औषधियों के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोविड काल में आर्सेनिक एल्बम-30 का व्यापक उपयोग किया गया। होम्योपैथी मन एवं शरीर के संतुलन पर कार्य करती है। डॉ. पिंकी ने होम्योपैथी एवं आयुर्वेद के समन्वित उपयोग से मिलने वाले लाभों को विस्तार से समझाया।

पार्षद दुष्यंत बख्शी ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर आमजन के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं तथा भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। जोगिंदर सिंह चौहान ने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि उन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति अपनाकर मधुमेह पर नियंत्रण पाया। यदि हम अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें तो स्वस्थ जीवन संभव है। अंत में जिला आयुष अधिकारी डॉ. मंजू शर्मा ने सभी अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति स्वरूप पौधे भेंट कर सम्मानित किया। शिविर के दौरान होम्योपैथिक ओपीडी में डॉ. महेंद्र, डॉ. मोनिका पूनिया व डॉ. आश्मी द्वारा मरीजों की जांच की गई तथा अरुण कुमार, विकास कुमार, अनुराधा व होम्योपैथिक फार्मासिस्ट जसबीर सिंह द्वारा निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। आयुर्वेदिक ओपीडी में डॉ. मीना व डॉ. अदिति द्वारा परामर्श दिया गया तथा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट धर्मवीर द्वारा औषधियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस प्रकार के शिविरों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नियमित रूप से होते रहने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद एवं होम्योपैथी का लाभ मिल सके।

इस अवसर पर होम्योपैथिक काउंसिलिंग मेंबर डॉ. रविंदर ऋषि, पार्षद, वार्ड नं. 13 दुष्यंत बख्शी, राजेंद्र वर्मा, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर-3 प्रधान रिंकू सैनी, आयुष विभाग के असिस्टेंट मनोज कुमार, जिला प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र कुमार, विभाग के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, अन्य अधिकारी-कर्मचारी, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

संपादकीय

डिजिटल जनगणना: 5.72 लाख परिवारों ने रचा इतिहास!

भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण में एक उत्साहजनक और ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है। भारत के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) ने यह जानकारी दी कि अब तक 5.72 लाख से अधिक परिवारों ने स्व-गणना (सेल्फ-एनुमरेशन) की सुविधा का उपयोग करते हुए अपनी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई है। यह आँकड़ा न केवल सरकार की डिजिटल पहल की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि भारत का आम नागरिक अब तकनीक को अपनाने में संकोच नहीं करता। जनगणना किसी भी देश की नीति-निर्माण प्रक्रिया की रीढ़ होती है। इससे प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएँ बनाती है। जब जनगणना के आँकड़े सटीक और व्यापक होते हैं, तो सरकार की नीतियाँ अधिक प्रभावी और लक्षित बनती हैं। इसीलिए जनगणना में आम जनता की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है और इस बार की डिजिटल पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव यह है कि नागरिकों को अपने घर बैठे ही अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने का विकल्प दिया गया है। पहले जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से जनगणना अधिकारियों पर निर्भर थी, जो घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करते थे। यह प्रक्रिया समय और संसाधन दोनों की दृष्टि से अत्यंत कठिन और खचीर्ली होती थी। परंतु डिजिटल स्व-गणना की सुविधा ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल, त्वरित और अधिक पारदर्शी बना दिया है। अब नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। महापंजीयक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जिन परिवारों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दी है, उन्होंने राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने का एक तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तरीका अपनाया है। यह बयान केवल एक प्रशासनिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश छिपा है – कि जनगणना केवल सरकारी आँकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। 5.72 लाख परिवारों की भागीदारी को यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह संख्या भले ही अभी प्रारंभिक लगे, लेकिन यह एक बड़े और सकारात्मक बदलाव की शुरूआत है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की आबादी 140 करोड़ से अधिक है और जहाँ डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी असमान है, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वेच्छा से डिजिटल माध्यम को अपनाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम धीरे-धीरे जमीनी स्तर पर अपनी जड़ें जमा रही है। डिजिटल जनगणना के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहली बात यह है कि इससे आँकड़ों की सटीकता में वृद्धि होती है। जब नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करते हैं, तो गलती की संभावना कम होती है। पारंपरिक जनगणना में जनगणना अधिकारी द्वारा मौखिक जानकारी को दर्ज करने में अनेक बार त्रुटियाँ हो जाती थीं। डिजिटल माध्यम में नागरिक स्वयं अपनी जानकारी की जाँच करके उसे सही कर सकते हैं, जिससे आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होता है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे जनगणना की प्रक्रिया की लागत में कमी आती है। करोड़ों की संख्या में जनगणना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने, उन्हें मानदेय देने और उनके द्वारा एकत्र किए गए कागजी आँकड़ों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में बहुत अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। डिजिटल स्व-गणना से इन सभी खर्चों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। तीसरा पहलू है नागरिकों की गोपनीयता और सुविधा। डिजिटल प्रक्रिया में नागरिक अपनी जानकारी अपनी सुविधानुसार और अपने घर की चारदीवारी में बैठकर दर्ज कर सकते हैं। उन्हें किसी अजनबी अधिकारी के सामने अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की असहजता का सामना नहीं करना पड़ता। हालाँकि, इस डिजिटल पहल के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में, स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच अभी भी सीमित है। इसके अलावा, बुजुर्ग नागरिकों और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना कठिन हो सकता है। इन चुनौतियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार केवल डिजिटल माध्यम पर ही निर्भर न रहे, बल्कि पारंपरिक जनगणना की प्रक्रिया को भी समानांतर रूप से जारी रखे। दोनों माध्यमों का संतुलित उपयोग ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि देश का कोई भी नागरिक जनगणना से बाहर न रह जाए। एक समावेशी जनगणना ही सटीक और उपयोगी होती है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल जनगणना प्रणाली में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। साइबर सुरक्षा के इस दौर में डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। यदि नागरिकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी जानकारी का दुरुपयोग नहीं होगा, तो डिजिटल जनगणना में भागीदारी और भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर, जनगणना 2027 का यह पहला चरण एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। 5.72 लाख परिवारों की स्वैच्छिक डिजिटल भागीदारी यह दशार्ती है कि भारत का समाज बदल रहा है और वह तकनीक को राष्ट्र-निर्माण के एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार कर रहा है। यह पहल न केवल जनगणना की प्रक्रिया को आधुनिक बनाती है, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच एक नई साझेदारी की नींव भी रखती है – एक ऐसी साझेदारी जिसमें हर नागरिक अपने देश के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस गति को बनाए रखे, डिजिटल साक्षरता का विस्तार करे और यह सुनिश्चित करे कि जनगणना 2027 देश की अब तक की सबसे व्यापक, सटीक और समावेशी जनगणना बने। तभी इस डिजिटल क्रांति का वास्तविक लाभ देश के हर कोने तक पहुँच सकेगा।

उपेक्षित आबादी बनाम वैश्विक एजेंडा
असली मुद्दे क्यों ओझल हो रहे हैं?

कैलाश चन्द्र (हि.स.)

भारत का सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य जितना विशाल है, उतना ही जटिल भी है। इस जटिलता के बीच आज हमारे सामने दो वास्तविकताएँ खड़ी हैं। पहली, भारत के ग्यारह करोड़ से अधिक घुमन्तु, अर्धघुमन्तु और डिनोटिफाइड जनजाति समुदाय जिन्हें डीएनटी, एनटी और एसएनटी के रूप में भी जाना जाता है, जोकि आज भी पहचान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय का मुद्दा है, जिसकी जनसंख्या लगभग पाँच से छह लाख मानी जाती है, किन्तु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमर्श में उसकी उपस्थिति अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की जा रही है। एक ओर इतनी विशाल आबादी है जो अदृश्य बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर एक छोटा समुदाय वैश्विक एजेंडों और वित्तीय तंत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय बहस को प्रभावित कर रहा है। इस विरोधाभास ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि क्या हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक एजेंडों का कब्जा हो रहा है।

भारत का जनजाति समाज गौरव, संघर्ष और उपेक्षा की एक लंबी कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। भारत की जनजातियाँ, चाहे वे अनुसूचित जनजाति हों या घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय, सदियों से भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग रही हैं। उनकी विवाह परम्पराएँ, कृषि-कौशल, वन-ज्ञान, संगीत और नृत्य की परम्परा, आत्मनिर्भर जीवन शैली और सांस्कृतिक स्वायत्तता, ये सभी भारतीय समाज के मूल स्वरूप से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन औपनिवेशिक दौर में इनके परिचय को लेकर जान-बूझकर भ्रम पैदा किया गया। मैक्समूलर और मैकाले जैसे विद्वानों ने इंडीजिनस, एबोरिजिनल और ट्राइब जैसे विदेशी शब्दों को थोपकर भारतीय जनजाति समाज को मुख्यधारा से अलग दिखाने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन के लिए इसका उद्देश्य स्पष्ट था, वन-संपदा, खनिज और भूमि पर अपना अधिपत्य स्थापित करना। उद्योगों के विस्तार के नाम पर वन समुदायों के अधिकारों को कमजोर किया गया और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (1871) जैसे कानूनों ने पूरे के पूरे समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया। यह कलंक आज भी कई क्षेत्रों में सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बना हुआ है।

स्वतंत्र भारत में भी यह उपेक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। रेंके कमीशन (2008) और इडेट कमीशन (2018) की रिपोर्टों के अनुसार देश में आठ से ग्यारह करोड़ के बीच घुमन्तु और डिनोटिफाइड जनजातियाँ हैं, किंतु अब तक किसी भी जनगणना में इन्हें अलग श्रेणी के रूप में स्थान नहीं मिला है। सत्तर से अस्सी प्रतिशत लोगों के पास स्थायी पता, पहचान पत्र या आवास संबंधी दस्तावेज तक नहीं हैं। सरकारी योजनाएँ इन तक पहुँच ही नहीं पातीं, जिससे शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। रोजगार और आजीविका के अवसर भी इनके लिए बेहद सीमित हैं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी आबादी अपनी बुनियादी पहचान तक से वंचित है, तब इसे राष्ट्रीय विमर्श में स्थान क्यों नहीं मिलता?

इसके विपरीत एलजीबीटीक्यू प्लस विमर्श का वैश्विक स्तर पर तीव्र उत्थान देखा जा रहा है। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि इस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की बुनियादी जिम्मेदारी है, किंतु जब हम तुलना के स्तर पर देखते हैं तो एक स्पष्ट असंतुलन सामने आता है। एक ओर पाँच से छह लाख की अनुमानित आबादी वाला समुदाय है, जिसे राष्ट्रीय विमर्श में अत्यधिक स्थान प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर आठ से ग्यारह करोड़ की घुमन्तु और डिनोटिफाइड जनजातियाँ हैं, जिन्हें लगभग नगण्य स्थान मिलता है। यह स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

अब इसे गहराई से समझें तो इसका एक उत्तर वैश्विक फंडिंग नेटवर्क में दिखाई देता है। फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन्स, रॉकफेलर नेटवर्क, ह्यूमन राइट्स फंड, यूएनडीपी इन्क्लूजन फंड और वैश्विक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तंत्र जैसी संस्थाएँ भारतीय विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया मंचों, सांस्कृतिक आयोजनों और डिजिटल अभियानों में भारी निवेश कर रही हैं। यह निवेश मुख्य रूप से एलजीबीटीक्यू प्लस और जेंडर फ्लुइडिटी जैसे एजेंडों के विस्तार के लिए किया जा रहा है। आँकड़े बताते हैं कि पिछले पाँच वर्षों में ऐसे विषयों पर आधारित कार्यक्रमों और उत्सवों में दो सौ से चार सौ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जिनमें साहित्यिक उत्सव, फिल्म समारोह, सामाजिक मीडिया संवाद और जेंडर आधारित चर्चाएँ प्रमुख हैं। इसके विपरीत यही समय अवधि ऐसी रही है, जिसमें घुमन्तु समाज पर राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा आयोजन देखने को नहीं मिला। ब्रांडिंग और वास्तविक मुद्दों के बीच यह अंतर भी इस असंतुलन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि एलजीबीटीक्यू प्लस विषय शहरी ब्रांडिंग के अनुकूल है, कॉरपोरेट प्रगतिशीलता के मॉडल से मेल खाता है। यह पश्चिमी राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप है और मीडिया तथा एलीट वर्ग के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बन चुका है, इसलिए इसे वित्तीय सहयोग और मंच उपलब्ध कराना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसके विपरीत घुमन्तु और डिनोटिफाइड जनजातियाँ न तो शहरी परिवेश का हिस्सा हैं, न ही उनके पास सामाजिक या डिजिटल प्रभाव है। वे बाजार या मीडिया के लिए तथाकथित रूप से आकर्षक नहीं मानी जातीं और न ही उनकी कहानी वैश्विक विमर्श के अनुरूप प्रस्तुत की जाती है। परिणामस्वरूप वे ब्रांड वैल्यू नहीं बन पातीं और विमर्श से बाहर रह जाती हैं।

पहुंच से प्राधिकार तक: नारीशक्ति को अगले दशक का भारत का निर्णायक सुधार बनाना

डॉ. संगीता रेड्डी

पिछले एक दशक में, भारत ने कुछ वैसा किया है जिसे कुछ ही देश बड़े पैमाने पर हासिल कर पाए हैं। भारत ने महिला सशक्तिकरण को इरादों से आगे जाकर बुनियादी ढांचे में बदल दिया है।

यह बदलाव कोई अनायास नहीं हुआ। यह सुनियोजित था। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, नीतिगत रूप से महिलाओं को विकास के केन्द्र में अधिक से अधिक रखा गया। ऐसा यह मानते हुए किया गया कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था में तेजी आती है।

इसके नतीजे सामने हैं। और इन नतीजों को मापा जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। इन खातों में से 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के हैं। इस कदम से लाखों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में पहली बार कदम रखने का मौका मिला है। लगभग 10 करोड़ महिलाएं, 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर, जमीनी स्तर पर उद्यमिता और स्थानीय आर्थिक मजबूती का वाहक बन रही हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंच चुकी है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हुए हैं और महिलाओं को अधिक समय लेने वाले श्रम से मुक्ति मिली है। ऋण तक पहुंच बढ़ी है और मुद्रा योजना के तहत दिए गए लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। महिला श्रमशक्ति की भागीदारी बढ़कर लगभग 37 प्रतिशत हो गई है। इससे महिलाओं की भागीदारी में लंबे समय से चला आ रहा गिरावट का रुझान अब उलट गया है।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसे कार्यक्रमों ने जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाया है और नाजुक स्थितियों में कमी लाई है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलों ने समाज में गहराई से पैठी सोच को बदलना शुरू कर दिया है।

अलग-अलग, ये सभी कार्यक्रम बेहद ठोस हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो, ये कार्यक्रम भारत में महिलाओं को देखने के नजरिए में आए एक संरचनात्मक बदलाव को दशार्ते हैं। महिलाओं को अब मात्र समर्थन पाने वाली के बजाय विकास के वाहक के रूप में देखा जा रहा है।

नीति निमार्ताओं और प्रशासकों के लिए, इसके सबक बिल्कुल साफ हैं: जब डिजाइन, कार्यान्वयन और जवाबदेही व्यवस्थित हों, तो व्यापक स्तर पर काम करना संभव होता है।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने काम के दौरान, मैंने देखा है कि जब प्रणालियां सैद्धांतिक मॉडलों के बजाय वास्तविक जरूरतों पर आधारित होती हैं, तो नतीजे बेहतर होते हैं। यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। जहां पहुंच सरल होती है, जहां वितरण में निरंतरता होती है और जहां नतीजों पर नजर रखी जाती है, वहां असर बिल्कुल साफ नजर आता है।

फिर भी, अगले चरण में और भी अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। क्योंकि हमारे सामने चुनौती अब नीति निर्माण की नहीं, बल्कि नीति के कार्यान्वयन की है।

कार्यक्रमों की व्यापकता के बावजूद, जागरूकता संबंधी कमजोरियां बनी हुई हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के आंकड़े एकसमान नहीं हैं। अंतिम छोर तक आपूर्ति अभी भी स्थानीय क्षमता पर ही निर्भर हैं। अवसर पाने वाली प्रत्येक महिला की दृष्टि से, ऐसी कई और महिलाएं हैं जो नीतिगत कमियों की वजह से नहीं, बल्कि पहुंच की कमी के कारण हाशिए पर बनी हुई हैं।

यहीं पर प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका निर्णायक हो जाती है।

हमें योजनाओं की घोषणाओं से आगे बढ़कर, उनकी व्यापकता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा। आउटपुट को मापने से आगे बढ़कर नतीजों पर नजर रखने की दिशा में बढ़ना होगा। पात्रता को कागज पर दर्ज करने से आगे जाकर व्यवहार में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जिला स्तर पर स्वामित्व, डेटा-आधारित निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होंगे। प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया को गति दे सकती है, लेकिन यह जमीनी जवाबदेही का स्थान नहीं ले सकती।

आज हर नीति निमार्ता के सामने बिल्कुल सीधा सा सवाल है: हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य महिला पीछे न छूटे?

यहीं पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे दौर के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बन सकता है।

विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर, नीति निर्माण को वास्तविक जीवन के अनुभवों के अनुरूप बनाने की संभावना पैदा होती है। महिला नेता समुदाय की वास्तविकताओं से जुड़ी अंतर्दृष्टि लेकर आती हैं - ऐसी अंतर्दृष्टि जो कार्यक्रमों को मजबूत कर सकती है, उनके कार्यान्वयन को बेहतर बना सकती है, लक्ष्यीकरण में सुधार कर सकती है और उन्हें तेजी से अपनाने में सहायक साबित हो सकती है।

उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्यान्वित किए जाने पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है: नेतृत्व में अधिक महिलाएं आ सकती हैं, अधिक उत्तरदायी नीतियां बन सकती हैं, उच्च भागीदारी और मजबूत नेतृत्व क्षमता का निर्माण संभव हो सकता है। इसी तरह सुधार अपने-आप सुदृढ़ होता जाएगा। इसी तरह आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य भी हासिल किए जा सकेंगे।

हम ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी द्वारा परिभाषित दशक में कदम रख रहे हैं। भारत के पास पहले से ही एक मजबूत आधार मौजूद है। यहां वैश्विक स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) की शिक्षा में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। इस उपलब्धि को बिना कोई समय गवांए स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान, उद्यम और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व में बदल देने का यही सही क्षण है।

पिछले दशक ने यह दशार्या है कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन के साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति का समन्वय होने पर क्या कुछ संभव हो सकता है। आज की ठोस बुनियाद पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन सशक्तिकरण को पहुंच से परे प्राधिकार तक ले जा सकता है।

लेकिन प्रतिनिधित्व को क्षमता में बदलना चाहिए और क्षमता का विकास संस्थागत समर्थन के जरिए होना चाहिए, ताकि कार्यान्वयन से सही नतीजे हासिल हो सकें।

अगले पांच वर्षों में, हमें महिलाओं को न केवल चुनावी रूप से, बल्कि संस्थागत रूप से भी नेतृत्व करने के लिए तैयार करने की दिशा में निवेश करना होगा। इसका सीधा मतलब है व्यवस्थित मार्गदर्शन, नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण, नीतिगत अनुभव और प्रभावी शासन को संभव बनाने वाली प्रशासनिक सहायता प्रणाली।

इसका मतलब यह भी है कि हमें नीति निर्माण के तरीकों पर नए सिरे से विचार करना होगा। कार्यक्रम सुलभ, समझने में आसान और तेज गति से कार्यान्वित किए जा सकने वाले होने चाहिए। नीतियों को जरूरत के हिसाब से विकसित करने के लिए फीडबैक प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए। और सफलताओं को केवल कवरेज से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आय, शिक्षा और सशक्तिकरण जैसे नतीजों में हुए बदलाव के आधार पर मापा जाना चाहिए। अब जबकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में यह कोई गौण मुद्दा नहीं है - यह हमारी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और संस्थागत प्रभावशीलता से सीधे जुड़ी हुई है।

इसलिए सफलता का असली पैमाना यह नहीं होगा कि हम कितनी योजनाएं बनाते हैं, बल्कि यह होगा कि हम कितने लोगों के जीवन को बदल पाते हैं।

अगर भारत पहुंच के मामले में संतृप्ति हासिल कर लेता है, भागीदारी को मजबूत करता है और नेतृत्व को सक्षम बनाता है, तो वह न केवल अपनी महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि अपने विकास की राह को भी नए सिरे से निर्धारित करेगा।

नीति निमार्ताओं और प्रशासकों के लिए जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ हैं। इन्हें पूरा करने का समय अब आ गया है।

(लेखिका अपोलो हॉस्पिटल्स में संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं)

आज का राशिफल

मेष: आज व्यापारिक क्षेत्र में आपको अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा।

वृषभ: आज अपने अधिकारों का गलत उपयोग करने से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। कीमती वस्तुओं के खोने या गुम होने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें। पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दोबारा उभर सकती हैं।

मिथुन: आज का दिन आनंद और सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। दोस्तों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी। हालांकि अत्यधिक उत्साह में कोई गलती हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें।

कर्क: व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप कहीं घूमने-फिरने का समय निकाल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। नए लोगों से जुड़ाव भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। व्यापार में नए अनुबंध मिलने के योग बन रहे हैं।

सिंह: आज स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें, खासकर गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है। वरिष्ठों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। निजी नौकरी करने वालों को आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दों पर चिंता हो सकती है।

कन्या: आज अपने काम की गुणवत्ता को बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। प्रशासनिक मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से हल्का और संतुलित भोजन करना फायदेमंद रहेगा।

तुला: आज प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है।

वृश्चिक: व्यापार में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। मानसिक शांति में कमी रहेगी। गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं उभर सकती हैं।

धनु: आज आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए लोन लेने का विचार कर सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे। परिवार और बच्चों के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन छवि सुधारने वाला हो सकता है।

मकर: कार्यस्थल पर अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे तनाव महसूस होगा। माता-पिता के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए संयम रखें। अंतिम समय में काम बिगड़ने की आशंका है। संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है।

कुंभ: आज कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है। आप सभी कार्यों को उत्साह और ऊर्जा के साथ पूरा करेंगे। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। बड़े भाई-बहनों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन समाज में आपकी छवि सकारात्मक रहेगी।

मीन: आज आपकी सोच और दृष्टिकोण से लोग प्रभावित होंगे। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने का निर्णय ले सकते हैं। भाइयों के साथ चल रहे संपत्ति विवाद समाप्त होने के संकेत हैं। यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।

भारतीयता में समाहित है वैश्विक कल्याण का मार्ग

प्रो. एस. के. सिंह (हि.स)

वर्तमान में अविश्वास की परतों से घिरी हुई विश्व व्यवस्था अनेक प्रकार के संघर्षों एवं अस्थिरताओं से जूझ रही है। ईरान बनाम अमेरिका-इजराइल युद्ध, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई असंगत कार्यवाही, लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध, पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव एवं बढ़ती असहिष्णुता इस बात का प्रमाण है कि आज विश्व गहरे संकट से गुजर रहा है।

वस्तुतः पिछले कुछ समय की सैन्य गतिविधियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि विश्व-व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है एवं धीरे-धीरे दुनिया 'जंगलराज' की ओर बढ़ रही है। टैरिफ को लेकर ट्रंप के अपरिपक्व एवं गैर-जिम्मेदार रवैये तथा पल-पल बदलते उनके बचकाने बयानों ने भूमंडलीकरण के मूल उद्देश्यों पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। जिस भूमंडलीकरण को परस्पर निर्भरता, वैश्विक सहयोग एवं साझा प्रगति का आधार माना गया था, आज वह कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन विषम परिस्थितियों में भारतीय दर्शन, भारत की संस्कृति अर्थात 'भारतीयता' एक ऐसा विकल्प है जो विश्व में स्थायी शांति, संतुलन, समन्वय एवं सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

हजारों सालों से पूरी पृथ्वी को एक मानने एवं मानवता के समग्र कल्याण पर आधारित 'वसुधैव कुटुम्बकम', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' जैसे भारतीय सिद्धांतों में विकास और प्रगति का अर्थ किसी एक व्यक्ति या किसी एक राष्ट्र का हित नहीं बल्कि समग्र रूप में पूरी मानवता का कल्याण करना है, अर्थात 'स्व' से 'सर्व' की यात्रा ही भारतीयता है। भारतीयता के इस मूल भाव को भारतीय जीवन दृष्टि के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारतीयता का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रकृति के साथ निकटता, सामंजस्य एवं संतुलन रखना है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में वृक्षों, नदियों, पर्वतों एवं धरती को पूजनीय माना गया है, जिसमें यह मान्यता है कि प्रकृति के साथ समन्वय रखकर ही पृथ्वी को बचाकर जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। सत्य, परोपकार, त्याग, दया, करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता, भक्ति, समर्पण, संयम और राष्ट्रप्रेम जैसे भारतीय जीवन मूल्य, मूल्य-आधारित भारतीयता की आत्मा हैं। कई तरह की विविधताओं के बावजूद 'अनेकता में एकता' भी भारतीयता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 'साईं इतना दीजिए जामें कुटुम्ब समाय' अर्थात हमें उतना ही संचय करना चाहिए, जितना आवश्यक है।

भारतीय मूल्यों की यह गहन अभिव्यक्ति भारतीयता के उस पहलू को उजागर करती है जहां व्यक्तिगत और सामूहिक हित साथ-साथ चलते हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य चिंतन के मूल में व्यक्ति, भौतिकता, बाहरी दुनिया एवं बाहरी उपलब्धियां हैं। इसलिए पश्चिम का मूल स्वभाव स्वार्थ है न कि सद्भाव। जिसके कारण कभी-कभी किसी एक व्यक्ति की अनैतिक एवं अनुचित महत्वाकांक्षाओं का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ईरान, अमेरिका-इजराइल युद्ध के चलते पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद होने का खतरा मंडरा रहा है।

अनगिनत लाभ के बावजूद अनियंत्रित लालच तथा विज्ञान एवं तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। भारत का स्पष्ट मानना है कि विज्ञान का उपयोग मानवता एवं मानव कल्याण के लिए होना चाहिए न कि व्यक्तिगत लाभ तथा भौतिक सुख-सुविधाओं की अंधी दौड़ एवं प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। यही कारण है कि 16 से 20 फरवरी, 2026 को दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' की थीम 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' रखी गई थी। इसके पूर्व नई दिल्ली में ही आयोजित जी-20 के शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम' थी, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया गया था।

स्पष्ट है कि भारत को जब भी दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, भारत ने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। चूंकि विस्तारवादी सोच की शुरूआत हमेशा लालच से होती है, इसलिए भारतीय चिंतन में इस सोच को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया गया। आध्यात्मिकता भारतीय चिंतन की मूल विशेषता है, इसलिए भारतीयता के हर पहलू में हमें इसकी झलक दिखाई देती है। सदियों से भारत में शिक्षा को विद्या, छात्र को विद्यार्थी एवं शिक्षक को गुरु कहा जाता था। शिक्षा हमें बाहरी ज्ञान एवं जीवनयापन सिखाती है, जबकि विद्या एक आंतरिक गुण है जो कि हमारे विवेक, संस्कारों एवं आचरण से जुड़ी होती है तथा हमें सही एवं गलत में भेद करना सिखाती है। शिक्षा सिर्फ सफलता तक सीमित रहती है जबकि विद्या हमें सार्थकता तक ले जाती है।

श्री विष्णु पुराण में उल्लेख है कि 'तत्कर्म यन्न बन्धाय, सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। यही कारण है कि भारतीयता में आत्म-बोध अर्थात आत्म-साक्षात्कार पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा वह है जिसे प्राप्त करने के बाद विनम्रता आए एवं व्यक्ति, व्यक्तिगत लाभ की जगह सामूहिक हित को प्राथमिकता दे, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है कि 'विद्या ददाति विनयं' अर्थात् सच्ची विद्या से व्यक्ति में विनम्रता आती है। भारतीय ज्ञान परंपरा त्याग, परोपकार एवं आत्मबोध पर आधारित होने के कारण संयम, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यबोध की भावना उत्पन्न करती है, जबकि पाश्चात्य ज्ञान परंपरा तर्क, विज्ञान एवं भौतिकता पर आधारित होने के कारण प्रतिस्पर्धा, अहंकार, श्रेष्ठता-बोध एवं आत्मकेन्द्रित बनाती है।

यहां स्पष्ट है कि दुनिया में यदि स्थायी शांति एवं सद्भाव स्थापित करना है तो हमें भारतीयता के मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना होगा। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अतीत की ओर लौटना ही भारतीयता नहीं है, बल्कि 'नित्य नूतन, चिर पुरातन' की सोच के साथ भविष्य के लिए एक संतुलित एवं मानवीय मार्ग का निर्माण करना भारतीयता का एक प्रमुख गुण है। यह केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

पर्यावरणीय असंतुलन, नैतिक पतन एवं सामाजिक विघटन के इस दौर में भारतीयता के मूल तत्वों से प्रेरित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'पंच परिवर्तन' न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि भारतीयता का मूल आधार भौगोलिक सीमाएं नहीं बल्कि समस्त जड़-चेतन एवं मानवता है। संघ के पंच परिवर्तन का किसी भी राजनीतिक दल द्वारा विरोध न किया जाना इसकी व्यापक स्वीकार्यता एवं सहमति का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारतीयता एवं संवैधानिक आदर्शों से प्रेरित सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी चेतना एवं नागरिक कर्तव्य ऐसे आधारभूत मूल्य हैं जो न केवल भारत के उत्थान तक सीमित हैं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हैं। स्वार्थ एवं संघर्ष में फंसी दुनिया के लिए भारतीयता ही एक मात्र विकल्प है।

ऐसे में कहना यही है कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन सभी का स्थायी समाधान भारतीयता पर आधारित शिक्षा में निहित है। ऐसी शिक्षा जो आधुनिकता को भारतीय पहचान से जोड़े भारतीय शिक्षा है। शिक्षा में भारतीयता का आशय सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं बल्कि वर्तमान से सामंजस्य स्थापित कर एक ऐसी जीवन दृष्टि प्रदान करना है जिसमें व्यक्ति यह समझ सके कि केवल विज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान एवं आध्यात्मिकता का सामंजस्य ही वैश्विक समस्याओं के स्थायी समाधान का मूल मंत्र है। आध्यात्मिकता एवं स्वीकार्यता भारतीयता की वे सार्वभौमिक विशेषताएं हैं जो भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक परिदृश्य में एक नई उम्मीद और विश्वास के केन्द्र के रूप में उभर रहा है।

(लेखक जीवाजी विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययनशाला में विभागाध्यक्ष हैं।)

नई औद्योगिक नीति 2026 से उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत: संजीव अरोड़ा

1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, स्थानीय सरकार और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने पटियाला में आयोजित एमएसएमई की जिला स्तरीय बैठक के दौरान उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह भी मौजूद थे।

स्थानीय सरकार विभाग को निर्देश जारी करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि शहरों में सफाई और सीवरेज व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि मई माह के अंत तक पंजाब के शहरी क्षेत्रों में ₹1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग योजना तैयार की गई है।

संजिव अरोड़ा ने यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार एक महीने के भीतर नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति लागू करेगी, जिसके तहत राज्य में कम से कम 25 एकड़ क्षेत्र में फैले बड़े औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के विकास में उद्योगपति और रियल एस्टेट डेवलपर संयुक्त रूप से भाग लेंगे, जबकि निवेशक इन परियोजनाओं में निवेश के लिए पंजीकरण कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे।

औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए मंत्री ने कहा कि सरकार नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति तैयार कर रही है, जो निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के प्लॉट उपलब्ध होंगे। बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने सरकार की नई नीतियों की सराहना की और उद्योगपतियों ने भी संतोष व्यक्त किया।

संजिव अरोड़ा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे फसलों को नुकसान हो या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हानि उठानी पड़े, सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

बिजली क्षेत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 100 प्रतिशत आवंटन किया जाता था, लेकिन अब बिजली बोर्ड स्वयं टेंडर जारी कर रहा है और इसमें काफी सफलता मिल रही है।

मंत्री ने आगे कहा कि नई औद्योगिक नीति 2026 के तहत फिल्म स्टूडियो, अस्पताल और होटल जैसे कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है क्योंकि यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब अब निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है और अन्य राज्य भी इन पहलों की सराहना कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जन-केंद्रित विकास सुनिश्चित करना है और उद्योग, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के माध्यम से पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।

इस अवसर पर समाना के विधायक चेतन सिंह जौड़ा माजरा, पटियाला शहरी के विधायक अजीतपाल सिंह कोहली, मेयर कुंदन गोगिया, डिप्टी मेयर हरिंदर कोहली, राज्य सचिव जगदीप जग्गा, नगर निगम आयुक्त परमजीत सिंह, एडीसी (शहरी विकास) नवरीत कौर सेखों, निदेशक उद्योग जसप्रीत सिंह, पंजाब राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र जीत सिंह, जीएम डीआईसी पटियाला अर्शदीप सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मान सरकार का बड़ा फैसला; विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए संचार की बाधाएं होंगी दूर

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने जरूरतमंद और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक और मानवीय तथा बाल हितैषी कदम उठाया है। बच्चों के लिए संवाद की सुविधा सुनिश्चित करने और भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु 42 स्पेशल एजुकेटर, 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और 48 अनुवादकों को पैनल में शामिल किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को अक्सर अपनी भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब ये विशेषज्ञ बच्चों और चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज के बीच संवाद को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ये स्पेशल एजुकेटर, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और अनुवादक बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, उनकी काउंसलिंग करने, पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करने तथा बच्चों को उनके परिवारों या अभिभावकों से पुनः जोड़ने में सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना भी है। इस पहल से विशेष जरूरतों वाले बच्चों की भावनाओं को समझने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बड़ी मदद मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए इस प्रकार के मानवीय कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं।

हरदीप सिंह मुंडियां ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पदोन्नति पत्र सौंपे

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

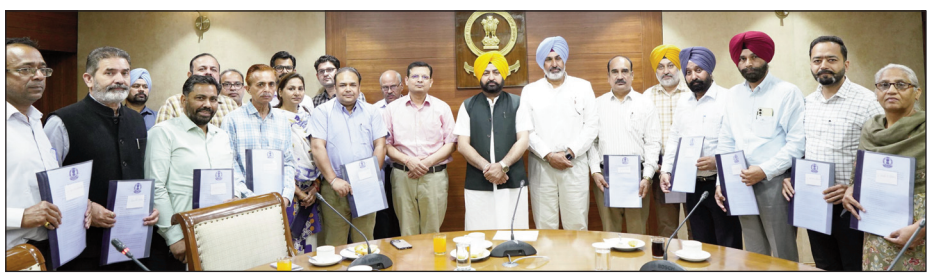

पंजाब के राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज पंजाब भवन में नव पदोन्नत राजस्व अधिकारियों को पदोन्नति पत्र वितरित किए।

राजस्व मंत्री ने वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले 14 तहसीलदारों और 13 नायब तहसीलदारों को बधाई देते हुए कहा कि ये पदोन्नतियां राज्य में राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाने के साथ-साथ अधिकारियों की मेहनत और वर्षों की सेवा का उचित सम्मान हैं। अधिकारियों को संबोधित करते हुए स. मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों को उनका अधिकार समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और योग्यता आधारित पदोन्नतियों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार होता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती उनके द्वारा दिए गए तीन पसंदीदा स्टेशनों में से एक पर उनके निवास स्थान के नजदीक की गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन सुनिश्चित करना है, ताकि अधिकारी अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें।

क्षेत्रीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए माल मंत्री ने विभाग के कामकाज में और सुधार के लिए अधिकारियों से सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से मिलने वाली फीडबैक नीतियों में सुधार और जवाबदेह व प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मान सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने जैसी पहलें भविष्य में भी जारी रहेंगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त राजस्व श्री अनुराग वर्मा ने भी नव पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी, समर्पण और पेशेवर तरीके से निभाते हुए जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 20 कैडेट एनडीए मेरिट सूची में शामिल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- कैडेट अभिश ने चौथा और गुरकरनजीत सिंह ने 12वां ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया
- अमन अरोड़ा ने कैडेटों को बधाई दी, कहा—यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में पंजाब के बढ़ते दबदबे का प्रमाण है

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने अपने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ते हुए 20 कैडेटों को सफलता दिलाई है। इन कैडेटों ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एस एस बी) इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास कर लिया है और जून 2026 में शुरू होने वाले प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस अकादमी (एन डी ए)-156 कोर्स की अंतिम मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है।

मोहाली के कैडेट अभिश ने ऑल इंडिया स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया, जबकि मलेरकोटला के कैडेट गुरकरनजीत सिंह ने 12वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा, संस्थान के कुल पांच कैडेटों ने राष्ट्रीय मेरिट सूची के शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई है। चयनित कैडेट अब नेशनल डिफेंस अकादमी, खड़कवासला से अपने जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं।

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में पंजाब के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कैडेटों की सराहना करते हुए कहा कि ये युवा पंजाब का गौरव हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन और संस्थान द्वारा दी गई उत्कृष्ट प्रशिक्षण ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी कैडेटों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई के निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अजय एच. चौहान, वीएसएम ने भी कैडेटों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम संस्थान की फैकल्टी की प्रतिबद्धता और कैडेटों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्कृष्ट अधिकारियों को तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

गैंगस्टरों ते वार का 80वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 449 स्थानों पर छापेमारी; 262 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ह्यगैंगस्टरों ते वारह्ण मुहिम के 80वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित 449 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू की गई एक विशेष मुहिम है। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें लगातार विशेष अभियान चला रही हैं। 80वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक हथियार बरामद करने के बाद 262 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

- पुलिस टीमों ने 76 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई, 75 को पूछताछ के बाद किया रिहा

इसके साथ ही इस मुहिम के तहत अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 20,156 तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त 76 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 75 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने इस दौरान 7 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों और आपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा करें। इस बीच, नशों के खिलाफ चल रही मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के 405वें दिन पुलिस ने 124 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.3 किलोग्राम हेरोइन, 36 किलोग्राम गांजा, 385 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 38,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इस मुहिम के तहत अब तक कुल 58,136 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 20 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया है।

राज चुनाव आयोग द्वारा 9 नगर निगमों और 104 नगर परिषदों के लिए आम/उपचुनाव संबंधी मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

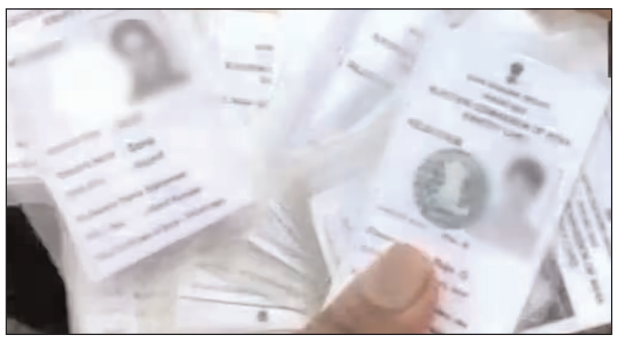

पंजाब राज्य में निकट भविष्य में होने वाले 9 नगर निगमों (बरनाला, बठिंडा, अबोहर, बटाला, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, एस.ए.एस. नगर और पठानकोट) तथा 104 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के आम एवं उपचुनाव-2026 के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस संबंध में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मौजूदा मतदाता सूचियां संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं, जहां-जहां नगर निकाय चुनाव होने हैं। यह संशोधन स्थानीय सरकार विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई वार्डबंदी के अनुसार किया जाएगा। संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों के योग्य मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम और विवरणों की पुष्टि अवश्य करें। यह सूची 15 अप्रैल 2026 को संबंधित जिलों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 (दोनों दिन शामिल) तक 7 दिन की अवधि निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, सभी डिप्टी कमिश्नरों को 20 और 21 अप्रैल 2026 को मतदाता नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 5 मई 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जो जिलों की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।

नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 23 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। अर्थात, जो भी व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पात्र होगा।

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म-7, 8 और 9) संबंधित एसडीएम-सह-निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, इन्हें आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

राज्य चुनाव आयोग ने आम जनता से अपील की है कि वे मतदाता सूची की शुद्धता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं तथा इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

संक्षिप्त-समाचार

पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने एम्स बठिंडा का दौरा किया

बठिंडा। पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बठिंडा का दौरा किया, जहाँ उनका स्वागत कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) रतन गुप्ता द्वारा किया गया। अपने दौरे के दौरान माननीय राज्यपाल ने संस्थान की आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने हार्ट कमांड सेंटर, इमरजेंसी वार्ड, ट्रायेज सुविधा, सर्जिकल ट्रॉमा वार्ड तथा सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट सहित प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान की आधुनिक अवसंरचना तथा मरीजों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने की तत्परता की सराहना की। फैकल्टी सदस्यों के साथ अपने संवाद में माननीय राज्यपाल ने मरीजों की देखभाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रति उनकी समर्पित भावना की सराहना की तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में एम्स बठिंडा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने संस्थान की प्रमुख पहलों, जैसे आउटरीच सेवाएं, प्रत्यारोपण कार्यक्रम, बाल एवं नवजात देखभाल, कैंसर देखभाल सेवाएं तथा मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए शेल्टर होम स्थापित करने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। माननीय राज्यपाल ने एम्स बठिंडा प्रशासन को अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोत्साहित किया तथा इस प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया। दौरे के समापन पर माननीय राज्यपाल ने समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के निरंतर प्रयासों की सराहना की।

भारत विकास परिषद जैतो ने आंखों का फ्री चैकअप कैंप लगाया, 9 मरीजों को आप्रेशन के लिए चुना गया

जैतो। इलाके की जानी-मानी मानवता को समर्पित समाज सेवी संस्था भारत विकास परिषद इकाई जैतो की तरफ से चौधरी सतपाल मित्तल की याद में एक फ्री आंखों का चैकअप कैंप लगाया गया। यह कैंप परिषद के अध्यक्ष रुलिया राम सिंगला और प्रोजैक्ट चेयरमैन प्रहलाद राय गर्ग के नेतृत्व में परिषद भवन में लायन आई केयर सैंटर जैतो के साथ मिलकर लगाया गया। इस कैंप में आंखों की स्पैशलिस्ट डॉ. कीर्ति सिंगला अपनी टीम प्रियंका और गुरप्रीत कौर के साथ खास तौर पर पहुंचीं और उन्होंने 95 मरीजों का चैकअप किया और फ्री दवाइयां दीं और 8 मरीजों को आप्रेशन के लिए चुना, जिनका ऑपरेशन सोमवार को लायन आई केयर सैंटर जैतो में मुफ्त किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद के कोषाध्यक्ष कृष्ण मित्तल, उपाध्यक्ष सतीश कुमार गोयल लांबा वाली वाले, ऑल प्रोजैक्ट चेयरमैन सुनील सिंगला, राज्य सदस्य मुकेश बांसल, सुरेश कुमार, रमेश मोंगा, सुरिंदर कुमार माहेश्वरी, सुरिंदर कुमार गर्ग एल.आई.सी .वाले,मेजर सिंह, राजीव गोयल बिट्टू बादल, प्रीतपाल सिंह रैडरोज, विक्की सिंगला भट्ठे वाले, डॉ.जसवीर सिंह धारीवाल, डॉ. विजय सिंगला, सुरिंदर वालिया, राज्य सदस्य संजय मित्तल, विजय सिंगला बिशनंदी वाले,परिषद के पी.आर.ओ.रिंकू बिंदल,लायन आई केयर सैंटर जैतो के कैंप चेयरमैन नरेश मित्तल,चौधरी राम रतन मित्तल परिवार सहित,लेडीज विंग अध्यक्ष प्रवीण गर्ग,आल प्रोजैक्ट लेडीज विंग चेयरमैन ममता जिंदल, ब्यूटी केयर सैंटर इंचार्ज अंजू मित्तल, सुनीता मित्तल, सिलाई टीचर मोनिका व मीनाक्षी पार्लर टीचर भावना मैडम आदि मौजूद थे।

योजना के तहत ₹300 करोड़ के ,2 लाख से अधिक उपचार;पंजाब बजट 2026झ्र27 में ₹2,000 करोड़ के आवंटन द्वारा समर्थित

स्वास्थ्य सेवाएँ पंजाब के हर नागरिक के लिए ; 'सेहत कार्ड' के लिए आयु, लिंग या आय की कोई बाधा नहीं : डॉ. बलबीर सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चिकित्सकीय आपात स्थिति अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती है; जो परिवारों को न केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, बल्कि इलाज के खर्च के बोझ की चिंता में धकेल देती है' इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ह्यमुख्यमंत्री सेहत योजनाह्ण की शुरूआत की, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के परिवार बिना किसी आर्थिक चिंता के समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकें।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता ह्यसेहत कार्डह्ण के माध्यम से साकार हो रही है, जो पूरे राज्य में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनमें विश्वास पैदा कर रहा है। गाँवों, कस्बों और शहरों में चल रहे व्यापक पंजीकरण अभियानों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

योजना की समावेशी प्रकृति और बढ़ती पहुँच को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, सेहत कार्ड सभी के लिए है; इसमें आयु, लिंग या आय की कोई बाधा नहीं है। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, अधिक परिवार कवरेज प्राप्त करने और अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से खुद को सुरक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें कैंसर उपचार, हृदय संबंधी हस्तक्षेप और अस्थि शल्य चिकित्सा (ऑर्थोपेडिक सर्जरी) जैसे महत्त्वपूर्ण उपचार शामिल हैं। अब तक इस योजना के तहत ₹300 करोड़ से अधिक लागत के उपचार प्रदान किए जा चुके हैं, जिसे और मजबूत करने के लिए पंजाब बजट 2026झ्र27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि इसके लाभों को बनाए रखा जा सके और उनका विस्तार किया जा सके, उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का नकदरहित उपचार प्राप्त होता है, जिससे किसी भी मरीज को आर्थिक बाधाओं या आपात स्थिति में पैसों की कमी के कारण इलाज में देरी न करनी पड़े।

अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बनाए गए हैं, जिन्हें औपचारिक केंद्रों तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है।

नागरिकों के लिए स्पष्ट रणनीति प्रदान करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजीकरण के लिए एक सरल छह-चरणीय प्रक्रिया भी निर्धारित की है। निवासी बिना किसी पूर्व नियुक्ति के निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर , सरकारी पंजीकरण शिविर या सेवा केंद्र पर सीधे जा सकते हैं। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे; ताकि परिवार के सभी सदस्य(जो पंजाब के निवासी होने चाहिए) योजना के अंतर्गत कवर हो सकें।

यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख की साझा कवरेज प्रदान करती है, इसलिए सभी सदस्यों का एक साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण स्थल पर अधिकारी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करते हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को सेहत कार्ड सक्रिय होने की पुष्टि हेतु एसएमएस (एस एम एस) प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त, सुगम पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हों) और किसानों के लिए जे-फॉर्म (यदि लागू हो) जैसे सहायक दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी जाती है। सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, पंजाब सरकार निवासियों को निर्दिष्ट केंद्रों और जमीनी स्तर के शिविरों के माध्यम से सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि हर परिवार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत नकदरहित उपचार का लाभ उठा सके।

सरल मार्गदर्शिका: छह चरणों में सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करें

चरण 1: किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं'- आप सीधे किसी केंद्र या शिविर में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

चरण 2: पंजीकरण स्थल पर जाएँ

आप जा सकते हैं : निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी) पर, सरकारी पंजीकरण शिविर पर, सेवा केंद्र पर

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज साथ लाएँ

परिवार के सभी सदस्यों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाएँ: आधार कार्ड, वोटर आईडी, नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण -पत्र, सभी सदस्य पंजाब के निवासी होने चाहिए

चरण 4: पारिवारिक कवरेज को समझें

यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कवर प्रदान करती है। यह राशि परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा होती है, इसलिए सभी के लिए दस्तावेज साथ लाना महत्त्वपूर्ण है।

नेपाल में मुक्तिनाथ दर्शन कर लौट रहे भारतीय तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 6 घायल

जलेश्वर के समीप अनियंत्रित होकर पलटी माइक्रोबस

घायलों में उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

नेपाल के प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल मुक्तिनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए शुक्रवार की सुबह अमंगलकारी रही। म्याग्दी जिले के बेनी नगरपालिका अंतर्गत जलेश्वर के पास एक इलेक्ट्रिक माइक्रोबस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार कुल 6 भारतीय यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को म्याग्दी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।

फोटोः हि.स.

जिला पुलिस कार्यालय म्याग्दी के अनुसार, यह घटना बेनी-जोमसोम-कोरला सड़क खंड पर घटित हुई। तीर्थयात्री मुस्तांग स्थित मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वापस लौट रहे थे। पुलिस निरीक्षक सागर तिमिल्सिना ने बताया कि बा 01-028 च 8436 नंबर की ईवी (इलेक्ट्रिक) माइक्रोबस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गई। प्रारंभिक जाँच में दुर्घटना का कारण सड़क की खराब स्थिति और मोड़ पर वाहन की गति अनियंत्रित होना माना जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। म्याग्दी जिला अस्पताल की सूचना अधिकारी झरना श्रेष्ठ ने मीडिया को बताया कि अस्पताल लाए गए छह घायलों में से एक की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल पोखरा स्थित उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र (मणिपाल शिक्षण अस्पताल) रेफर कर दिया गया है। शेष पांच यात्रियों का उपचार बेनी के प्रादेशिक अस्पताल में किया जा रहा है, जहाँ उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। दुर्घटना में उत्तरप्रदेश के 26 वर्षीय दीना मादी, 36 वर्षीय त्रिवेणी भारत, 50 वर्षीय प्रमोद शंकर यादव, 28 वर्षीय कैलाश देयानी, 70 वर्षीय निरंजन दास खन्ना और 22 वर्षीय सन्तोष घायल हुए हैं। म्याग्दी के जिला प्रमुख ने कहा है कि जलेश्वर खंड पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क विभाग को सुरक्षा बोर्ड लगाने और गड्ढों को भरने के निर्देश दिए गए हैं।

जलेश्वर बना 'ब्लैक स्पॉट': तीन दिन में दूसरा हादसा

स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय जलेश्वर क्षेत्र में बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं हैं। इसी स्थान पर बुधवार को भी एक भीषण टक्कर हुई थी, जिसमें ट्रक और बस के आपस में टकराने से मुक्तिनाथ से लौट रहे 15 भारतीय तीर्थयात्री घायल हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के इस हिस्से में तीखे मोड़ और सुरक्षा अवरोधकों की कमी के कारण वाहन चालक अक्सर नियंत्रण खो देते हैं।

मप्र के उज्जैन में खुले बोरवेल के गड्ढे में गिरा दो साल का बच्चा, बचाव अभियान जारी

एजेंसी (हि.स.)

भोपाल

फोटोः हि.स.

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 75 किमी दूर बड़नगर इलाके के पास ग्राम झालरिया में गुरुवार रात बोरवेल के खुले गड्ढ़े में गिरे दो साल का मासूम बच्चे को बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन 75 फीट की गहराई पर मिली है। पांच पोकलेन मशीनों की मदद से बोरवेल के समानांतर सुरंग बनाई जा रही है। खबर लिखे जाने तक करीब 40 फीट खुदाई हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार, भेड़े चराने के लिए आया राजस्थान के पाली जिले के एक परिवार का दो साल का बच्चा गुरुवार रात करीब साढ़े सात बजे बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम, हरदा, इंदौर और उज्जैन की एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। मौके पर दो एंबुलेंस भी तैनात हैं। बड़नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि बोरवेल में गिरने वाला दो वर्षीय मासूम भागीरथ पुत्र प्रवीण देवासी ग्राम गुडानला, जिला पाली (राजस्थान) का रहने वाला है। परिवार पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था। परिजन के मुताबिक, बच्चा दीवार के पास खेल रहा था। उसने पत्थर से बोरवेल का ढक्कन हटाया और बाल्टी समझकर पैर डाल दिया, जिससे वह सीधे अंदर गिर गया। बच्चे की मां ने उसे गिरते देखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गहराई में जा चुका था। परिवार ने गांव के सरपंच को सूचना दी। इसके बाद जिला प्रशासन को जानकारी दी गई। रात करीब साढ़े आठ बजे एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। भोपाल, इंदौर, हरदा और उज्जैन से आए 200 लोगों की रेस्क्यू टीम भागीरथ के बोरवेल से निकालने की कोशिश में जुटी है। जानकारी मिलने पर उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि बोरवेल करीब 200 फीट गहरा है, जिसमें बच्चा 75 फीट की गहराई पर अटका है।

सर्राफा बाजार में फिसला सोना, चांदी की भी घटी चमक

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार शुरूआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख नजर आ रहा है। सोना शुक्रवार के शुरूआती कारोबार की तुलना में 2,170 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। इसी तरह चांदी कीमत में भी कल के शुरूआती कारोबार की तुलना में 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमजोरी दर्ज की गई है।

सोने की कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना शुक्रवार 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना शुक्रवार 1,38,840 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु शुक्रवार दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में शुक्रवार 24 कैरेट सोना 1,51,620 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,51,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,890 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना शुक्रवार 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,38,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना शुक्रवार 1,51,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,38,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,38,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,51,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी शुक्रवार सोने के भाव में कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है।

नेपाल में एक महीने के दौरान तेल की कीमते चौथी बार बढ़ाने का फैसला

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

नेपाल में एक महीने के भीतर चौथी बार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में भारी वृद्धि की गई है। नेपाल आयल निगम ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं।

निगम के निदेशक मंडल के निर्णय के बाद नई दरें आज शुक्रवार से लागू हो गई हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, खाना पकाने वाला एलपीजी गैस और विमान ईंधन–सभी के दाम बढ़ाए गए हैं।

संशोधित दरों के अनुसार, पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 17 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल और केरोसिन में प्रति लीटर 25-25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खाना पकाने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की वृद्धि हुई है और घरेलू विमान ईंधन 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतों के अनुसार,

फोटोः हि.स.

नेपाल में अब पेट्रोल 219 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल और केरोसिन 207 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,010 रुपये और घरेलू विमान ईंधन 257 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। सरकार ने कहा है कि सीमा शुल्क और अवसंरचना विकास कर में 50 प्रतिशत की कटौती के बावजूद लगातार हो रहे नुकसान के कारण कीमत बढ़ाना आवश्यक हो गया था। निगम के द्वारा जारी बयान के अनुसार, ताजा मूल्य वृद्धि के बाद भी हर पखवाड़े लगभग 7.81 अरब रुपये का घाटा होने का अनुमान है। पिछले एक महीने में यह चौथी बार है जब नेपाल आयल निगम ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के भारी वृद्धि की है। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण तेल आयात में आई कमी को देखते हुए लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ पर लगने वाले सरकारी टैक्स में ५० प्रतिशत कम करने का फैसला भी लिया लेकिन इससे इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं आई और जनता को उससे राहत नहीं मिल पाई है।

संक्षिप्त-समाचार

शुरूआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बीच शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बने तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही कोशिश का असर घरेलू शेयर बाजार में भी नजर आ रहा है। इस कोशिश की वजह से आज शुरूआती कारोबार के दौरान बाजार में मजबूती का रुख बना हुआ है। आज के कारोबार की शुरूआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद लिवालों और बिकवालों के बीच एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में उतार-चढ़ाव होने लगा। हालांकि अभी तक के कारोबार में लिवालों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.94 प्रतिशत और निफ्टी 0.92 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। आज सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, जियो फाइनेंशियल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 2.78 प्रतिशत से लेकर 1.69 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, सन फार्मास्युटिकल्स, इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर 2.94 प्रतिशत से लेकर 1.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,693 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 2,441 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 252 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 24 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर छह शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 41 शेयर हरे निशान में और नौ शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे।

राशन घोटाला मामले में ईडी ने राज्य के 12 ठिकानों पर की छापेमारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार सुबह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कोलकाता, हावड़ा, बनगांव और मुर्शिदाबाद सहित राज्य के कुल 12 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी राशन वितरण की प्रक्रिया और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है। कोलकाता में बसंत कुमार रोड स्थित एक व्यवसायी के आवास पर सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे। यहां राशन वितरण के तौर-तरीकों और आपूर्ति के नेटवर्क को लेकर संबंधित व्यवसायी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शहर के पोद्दार कोर्ट और मिंटो पार्क इलाके में भी कई स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है। दूसरी ओर, रानीगंज में अजय कोयाल नामक व्यवसायी के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। अजय कोयाल का रानीगंज में लंबे समय से चावल का कारोबार है, जिसका विस्तार राज्य के अलावा देश के अन्य हिस्सों तक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, वह विदेशों में भी चावल की आपूर्ति करते हैं। शुक्रवार सुबह केंद्रीय बलों के साथ चार वाहनों में पहुंचे अधिकारियों ने अजय कोयाल के आवास पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई को राशन घोटाला मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले समय में इससे जुड़े और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए किया गया नामित

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नामित सदस्य नियुक्त किया है' शुक्रवार को जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एक सदस्य की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुई सीट पर राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था। यह रिक्ति भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद उत्पन्न हुई थी। सरकार की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उसी अनुच्छेद के खंड (3) के तहत राष्ट्रपति हरिवंश को राज्यसभा (परिषद्-ए-राज्य) का सदस्य नामित करते हैं, ताकि नामित सदस्य के सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्ति को भरा जा सके। उल्लेखनीय है कि हरिवंश एक जाने-माने पत्रकार रहे हैं। वे लंबे तक हिंदी अखबार प्रभात खबर के प्रधान संपादक रहे और पत्रकारिता में उनकी अलग पहचान रही है। फिर वे जनता दल यूनाइटेड के साथ राजनीति से जुड़े। उन्हें 2014 में बिहार से राज्यसभा सदस्य बनाया गया। हरिवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए। इसके बाद फिर 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए थे। उनका अगला कार्यकाल 2032 तक रहेगा। संसद में उनकी भूमिका संतुलित और शांत तरीके से काम करने वाली मानी जाती है। इस बार फिर से राष्ट्रपति की ओर से सदस्य नियुक्त किया गया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से तोड़ा गठबंधन, अकेले लड़ने का ऐलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है और राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शुक्रवार तड़के सोशल मीडिया पर जारी बयान में पार्टी ने कहा कि वह किसी ऐसे विवाद या बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती, जिससे मुस्लिम समुदाय के आत्मसम्मान पर प्रश्न उठे। बयान में स्पष्ट किया गया कि आज से हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन समाप्त किया जाता है। इस फैसले को हुमायूं कबीर से जुड़े कथित ह्यगोपनीय वीडियोह्न विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बयान में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इसी विवाद के बाद दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ी। गठबंधन टूटने पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उनके मन में ओवैसी के प्रति व्यक्तिगत सम्मान पहले भी था और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 25 मार्च को कोलकाता में हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था।

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश -रविवार को ओपीडी का करे संचालन

काठमांडू। नेपाल सरकार ने देशभर के अस्पतालों में रविवार को भी बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवा संचालित करने का निर्देश दिया है। सप्ताह में दो दिन अवकाश देने के सरकारी निर्णय के बाद रविवार को अस्पताल सुनसान होने लगे थे, जिसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। दो दिन के साप्ताहिक अवकाश के निर्णय के लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों ने रविवार को ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं। लेकिन दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रविवार को अस्पताल पहुंचकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। जनस्तर पर तीखी आलोचना होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीच का रास्ता अपनाया है। मंत्रालय के सह-प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा, ह्लकार्यभार और उपलब्ध जनशक्ति का प्रबंधन करते हुए रविवार को भी अनिवार्य रूप से ओपीडी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने अस्पताल प्रशासन को कुछ विकल्प भी दिए हैं, जिनमें रविवार को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों या चिकित्सकों को शनिवार के अलावा सप्ताह के किसी अन्य दिन बदले में छुट्टी देने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

पाकिस्तानी रक्षामंत्री के बयान पर इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया- आतंकियों से देश की रक्षा करते रहेंगे

एजेंसी (हि.स.)

तेल अवीव

अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को इस्लामाबाद में प्रस्तावित बैठक से पहले इजराइल और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री की टिप्पणी ने इजराइल को असहज कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लेबनान पर हमले के संदर्भ में इसराइल को 'कैंसर राष्ट्र' कहा, जिसे इजराइल ने 'शर्मनाक और निंदनीय' कहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। तेल अवीव और इस्लामाबाद के बीच बयानों की कड़वाहट नये सिरे से उस समय बढ़ी जब गुरुवार को पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इजराइल को

Prime Minister of I... @IsraeliPM Follow

The Prime Minister's Office:

Pakistan Defence Minister's call for Israel's annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace.

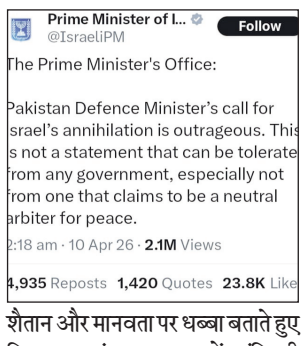

2:18 am · 10 Apr 26 · 2.1M Views

4,935 Reposts 1,420 Quotes 23.8K Likes

शैतान और मानवता पर धब्बा बताते हुए लिखा- जहां इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं वहां वो लेबनान में जनसंहार कर रहा है। पहले गाजा में निर्दोष लोगों को मार रहा था और अब लेबनान में यही कर रहा है। जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर इस कैंसरनुमा देश को बनाया है वो जहन्नुम में जलें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कार्यालय ने एक्स पोस्ट कर पाकिस्तानी रक्षामंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इसराइल के खात्मे की कामना बेहद आपत्तिजनक है। खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति का मध्यस्थ बताती हो, उससे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। इजराइल के विदेश मंत्री डिगियन सार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इजराइल रशांति की मध्यस्थतार करने का दावा करने वाली सरकार की यहूदी विरोधी खूनी आरोपों को बहुत गंभीरता से देखता है। यहूदी राज्य को रकैंसरग्रस्तर कहना प्रभावी रूप से विनाश का आह्वान है। इजराइल उन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा जो इसे नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। इससे पहले इजराइल ने बुधवार रात लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले करते हुए 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि ईरान में युद्धविराम के बावजूद लेबनान के हथियारबंद गुट हिज्बुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी है।

भारतीय विदेश सचिव ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात, अगले माह भारत आने वाले हैं रूबियो

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

वॉशिंगटन

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद थे। रूबियो अगले माह भारत के दौरे पर आने वाले हैं।

तीन दिवसीय अमेरिका दौरे पर पहुंचे विक्रम मिसरी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस मुलाकात को लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने विक्रम मिसरी को टैग करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- मार्को रूबियो के साथ सार्थक बैठक हुई जिसमें विशेषकर ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और क्वाड को लेकर बात हुई। रुबियो अगले महीने भारत आने के लिए उत्साहित हैं।

इससे पहले विक्रम मिसरी ने अमेरिका के विदेश उप सचिव क्रिस्टोफर लैंडाउ से भी मुलाकात कर फारस की खाड़ी की स्थिति, अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत की।

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत एशिया में भी तेजी का रुख

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के एक बार फिर पटरी पर लौटने की खबर से दुनिया भर के बाजार का मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच जारी जंग के थमने की उम्मीद की वजह से बाजार में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार आज चौतरफा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं।

पश्चिम एशिया में जारी जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही कोशिश के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 275.88 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 48,185.80 अंक तक पहुंच गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,824.66 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 186.66 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 22,821.66 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.03 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 48,200.25 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,603.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

परिणाम | असम बोर्ड 10वीं के परिणाम घोषित

65.62% छात्र सफल, ज्योतिर्मय दास ने किया टॉप

4.29 लाख छात्रों में से 2.81 लाख हुए उत्तीर्ण; डिमा हसाओ जिला रहा सबसे आगे

एजेंसी (हि.स.)

गुवाहाटी

असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को (एचएसएलसी) परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए, जिसमें कुल 65.62 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण रहे। परीक्षा में शामिल हुए 4,29,249 छात्रों में से 2,81,701 छात्र सफलतापूर्वक पास हुए।

ये परीक्षाएं 10 से 27 फरवरी तक आयोजित की गई थीं, जबकि नतीजे 10 अप्रैल को घोषित किए गए। कुल 4,38,564 विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 9,315 अनुपस्थित रहे और 135 को परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निष्कासित कर दिया गया। पांच नतीजे रोक दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वालों में 1,86,468 छात्र और 2,42,781 छात्राएं थीं। प्रदर्शन के मामले में, छात्रों का पास प्रतिशत 67.78 रहा, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 63.96 रहा।

डिवीजन वार आंकड़ों के अनुसार, 85,189 छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की, जिनमें से 3,983 ने डिस्टिंक्शन और 13,681 ने स्टार मार्क हासिल किए। कुल 1,50,167 उम्मीदवार द्वितीय श्रेणी में पास हुए, जबकि 46,345 ने तृतीय श्रेणी हासिल की। विभिन्न विषयों में 99,062 उम्मीदवारों ने लेटर मार्क हासिल किए। डिमा हसाओ 88.23 पास प्रतिशत के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा, जिसके बाद शिवसागर 84.08 प्रतिशत और डिब्रूगढ़ 78.46 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कछार जिले का पास प्रतिशत सबसे कम 49.13 प्रतिशत रहा। श्रेणी-वार आंकड़ों के अनुसार, एसटी (पी) उम्मीदवारों का पास प्रतिशत सबसे अधिक 73.65 प्रतिशत रहा, जिसके बाद ओबीसी (71.65 प्रतिशत) और एमओबीसी (70.94 प्रतिशत) रहा। चाय जनजाति (टी ट्राइब) के उम्मीदवारों का पास प्रतिशत सबसे कम 50.51 प्रतिशत रहा। मेरिट लिस्ट में, बजाली ज़िले के पटाचारकुची स्थित शंकरदेव शिशु निकेतन के ज्योतिर्मय दास ने पहला स्थान हासिल किया। बिस्वनाथ जिले के अंबिकागिरी राय चौधरी जातीय विद्यालय की आकांक्षा भुइयां, डिब्रूगढ़ जिले के लिटिल फ्लावर एचएस स्कूल की जिया फराह इस्लाम और नलबाड़ी के लिटिल फ्लावर्स स्कूल के सुरजीत अख्तर शीर्ष चार रैंक धारकों में शामिल हैं। इन नतीजों की घोषणा असम भर के लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि है।

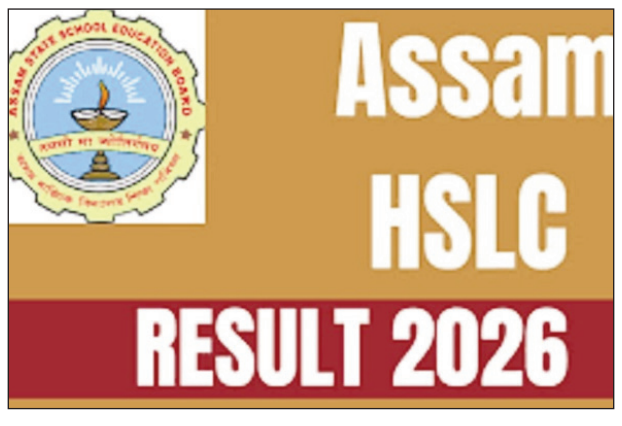

बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड से हार के बाद यूईएफए में शिकायत दर्ज कराई

पेनल्टी न मिलने से नाराज बार्सिलोना ने मैच संचालन पर उठाए सवाल; जांच की आधिकारिक मांग

हैंडबॉल' के स्पष्ट मामले में निर्णायक और वीएआर की चुप्पी पर क्लब ने जताई कड़ी आपत्ति

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

स्पेन के क्लब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड से 0-2 की हार के बाद मैच संचालन को लेकर गुरुवार को यूईएफए में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

विवाद दूसरे हाफ की शुरूआत में हुई एक घटना को लेकर है, जब बार्सिलोना ने पेनल्टी की मांग की थी। आरोप है कि एटलेटिको के गोलरक्षक जुआन मुस्सो ने गोल किक के बाद गेंद को खेल में ला दिया था, लेकिन इसके बाद डिफेंडर मार्क प्यूबिल ने छह गज क्षेत्र के अंदर हाथ से गेंद को छू लिया। मैच के निर्णायक इस्तवान कोवाक्स ने इस पर खेल जारी रखा और वीडियो सहायक प्रणाली ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे बार्सिलोना के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ में नाराजगी देखी गई। क्लब ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उनके कानूनी विभाग ने इस मामले को लेकर यूईएफए में शिकायत दर्ज कराई है। क्लब के अनुसार, 54वें मिनट में खेल सही तरीके से शुरू होने के बाद विरोधी खिलाड़ी द्वारा गेंद को हाथ से उठाना स्पष्ट रूप से दंड का मामला था, लेकिन इसे नहीं दिया गया।

फोटोः हि.स.

बार्सिलोना ने इस फैसले को बड़ी त्रुटि बताते हुए जांच की मांग की है। साथ ही निर्णायक और वीडियो सहायक प्रणाली के बीच हुई बातचीत तक पहुंच देने और गलती होने की स्थिति में आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार करने की मांग भी की है। इस तरह की घटनाओं में पहले भी अलग-अलग निर्णय सामने आए हैं। अप्रैल 2024 में चैंपियंस लीग के एक मुकाबले में बायर्न म्यूनिख को आर्सेनल के खिलाफ ऐसी ही स्थिति में दंड नहीं मिला था, जब गैब्रियल मगलाएस ने गेंद को छुआ था।

वहीं 2024 में ही एक अन्य मुकाबले में वीडियो सहायक प्रणाली ने हस्तक्षेप करते हुए क्लब ब्रुगे को दंड दिया था, जब एस्टन विला के गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेज और डिफेंडर टायरोन मिंग्स से जुड़ा समान मामला सामने आया था।

जोएल एम्बीड की आपात सर्जरी प्लेऑफ में खेलना संदिग्ध

एजेंसी (हि.स.)

ह्यूस्टन

नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) फ्रेंजाइजी फिलाडेल्फिया 76र्स के स्टार खिलाड़ी जोएल एम्बीड की गुरुवार को ह्यूस्टन में अपेंडिक्स की आपात सर्जरी हुई। टीम ने पुष्टि की कि उन्हें रात में अचानक अपेंडिसाइटिस की समस्या हुई, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा।

फोटोः हि.स.

यह सर्जरी उस समय हुई जब फिलाडेल्फिया 76र्स की टीम ह्यूस्टन रॉकेट्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रही थी। टीम के मुख्य कोच निक नर्स ने बताया कि बुधवार के अभ्यास के दौरान एम्बीड बिल्कुल ठीक थे, लेकिन गुरुवार तड़के करीब 3 बजे उन्होंने अस्वस्थ महसूस होने की जानकारी दी। कोच के अनुसार, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां जांच के बाद सर्जरी करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल एम्बीड की वापसी को लेकर कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन प्ले-इन टूर्नामेंट और प्लेऑफ के शुरूआती मुकाबलों में उनके खेलने की संभावना कम मानी जा रही है। यह टीम के लिए बड़ा झटका है। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में फिलाडेल्फिया 76र्स की टीम आठवें स्थान पर है और प्ले-इन में जगह बनाने की स्थिति में है, जबकि छठे स्थान की टीम से केवल एक मैच पीछे है। एम्बीड ने इस सत्र में केवल 38 मैच खेले हैं, जिसका मुख्य कारण उनके घुटने से जुड़ी समस्या रही है। इसके बावजूद उन्होंने सैन एंटोनियो स्पर्स के खिलाफ मुकाबले में 34 अंक और 12 रिबाउंड का शानदार प्रदर्शन किया था। इस सीजन में एम्बीड औसतन 26.9 अंक और 7.7 रिबाउंड बना रहे हैं। 2022-23 सत्र में उन्होंने 33.1 अंक के औसत के साथ सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब जीता था। उनकी अनुपस्थिति में टीम को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। कोच निक नर्स ने कहा कि टीम के पास एडेम बोना और आंद्रे ड्रमंड जैसे विकल्प मौजूद हैं, जिनका उपयोग किया जाएगा। हाल ही में एम्बीड ने एक मुकाबले में नहीं खेलने दिए जाने पर नाराजगी भी जताई थी और इसके लिए टीम प्रबंधन की ओर इशारा किया था। अब प्लेऑफ से पहले टीम पर दबाव बढ़ गया है। कोच ने कहा कि टीम को खुद को संभालना होगा और पेशेवर तरीके से हालात का सामना करना होगा।

पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी जिम्बाब्वे महिला टीम

खेलेगी छह मैचों की सफेद गेंद सीरीज

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

10 अप्रैल (हि.स.)। जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम अपने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान दौरे पर जाने के लिए तैयार है, जहां वह तीन एकदिवसीय और तीन टी20 मुकाबलों की श्रृंखला खेलेगी। यह सभी मुकाबले कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला 3 मई से शुरू होगी, जो आईसीसी महिला चैम्पियनशिप 2025-29 का हिस्सा है। इसके बाद 12 मई से टी20 श्रृंखला खेली जाएगी।

पाकिस्तान महिला टीम इस समय महिला चैम्पियनशिप तालिका में पांचवें स्थान पर है। टीम को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जिम्बाब्वे महिला टीम सातवें स्थान पर है और उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में हार मिली थी। जिम्बाब्वे टीम 29 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी और श्रृंखला की तैयारियां शुरू करेगी।

फोटोः हि.स.

कार्यक्रम इस प्रकार है

एकदिवसीय सीरीजः-
3 मईः पहला एकदिवसीय मुकाबला
6 मईः दूसरा एकदिवसीय मुकाबला
9 मईः तीसरा एकदिवसीय मुकाबला

टी 20 सीरीज

12 मईः पहला टी20 मुकाबला
14 मईः दूसरा टी20 मुकाबला
15 मईः तीसरा टी20 मुकाबला

फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026: जावोखिर सिंदारोव शीर्ष पर बरकरार, आर. वैशाली को बढ़त, दिव्या देशमुख को हार

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

साइप्रस में चल रहे फिडे कंडीडेट्स टूर्नामेंट 2026 के दसवें दौर में ओपन वर्ग में जावोखिर सिंदारोव ने आर. प्रज्ञानानंद को हराकर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। सिंदारोव अब आठ अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं और उन्होंने प्रज्ञानानंद के खिलाफ दूसरी जीत भी दर्ज की। मुकाबले की शुरूआत में प्रज्ञानानंद ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन 22वीं चाल में की गई एक गलती (इ7) उनके लिए भारी साबित हुई। इसके बाद सिंदारोव ने 23. फ7 चाल चलकर जोरदार हमला किया और आगे की सटीक चालों से स्थिति पूरी तरह अपने पक्ष में कर ली। अंततः प्रज्ञानानंदा को हार माननी पड़ी।

अन्य मुकाबलों में अनीश गिरी और हिकारू नाकामुरा के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, जिससे सिंदारोव को दो अंकों की बढ़त मिल गई। वहीं आंद्रेई एसिपेंको और मथियास ब्लूबाउम के बीच भी बाजी

बराबर रही, जबकि फाबियानो कारुआना और वेई यी ने भी अंक साझा किए। महिला वर्ग में आर. वैशाली ने अन्ना मुजिचुक के खिलाफ संतुलित खेल दिखाते हुए मुकाबला बराबरी पर खत्म किया और छह अंकों के साथ बढ़त हासिल की। उन्होंने विरोधी के हमलों को समझदारी से रोका और अंत में स्थिति पूरी तरह संतुलित कर दी। वहीं दिव्या देशमुख को जीती हुई बाजी गंवानी पड़ी। समय के दबाव में हुई गलती का फायदा उठाते हुए अलेक्जेंड्रा गोयाचकिना ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अन्य मुकाबलों में कातेरिना लाग्नो और तान झोंगयी के बीच बाजी बराबर रही, जबकि बिबिसारा अस्साउबायेवा ने झू जिनर को हराया।

हॉकी इंडिया ने टिम व्हाइट को भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में टिम व्हाइट की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के इस अनुभवी कोच ने हाल ही में जनवरी 2026 में हीरो हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स टीम के मुख्य कोच के रूप में काम किया था। अब वह भारत की उभरती हुई युवा प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी संभालेंगे। टिम व्हाइट का कोचिंग करियर काफी प्रभावशाली रहा है। भारत आने से पहले वह बेल्जियम की अंडर-21 महिला टीम के कोच थे, जहां उन्होंने टीम को दिसंबर 2025 में जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक दिलाया। इसके अलावा 2021 से 2024 के बीच वह बेल्जियम की सीनियर महिला टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे, इस दौरान टीम की विश्व रैंकिंग 12वें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान तक पहुंची और 2024 पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम के राष्ट्रीय कोच भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक हासिल किया था। अपनी नियुक्ति पर टिम व्हाइट ने कहा कि भारत में हॉकी के प्रति जुनून और समृद्ध परंपरा ने उन्हें दोबारा यहां आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वह यहां की युवा प्रतिभाओं को नजदीक से देख चुके हैं और उनका लक्ष्य ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है, जो तकनीकी रूप से मजबूत हों और सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए तैयार रहें।

टीम को लेकर अपनी योजना साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वह खेल को सरल रखते हुए टीम की सामूहिक और व्यक्तिगत ताकत पर ध्यान देंगे। उनका लक्ष्य एक ऐसी टीम तैयार करना है जो आक्रामक हॉकी खेले, लेकिन रक्षण में भी अनुशासन बनाए रखे। साथ ही उन्होंने फिटनेस और दबाव में बेहतर प्रदर्शन को भी प्राथमिकता दी। टिम व्हाइट की नियुक्ति को भारतीय हॉकी में आधुनिक रणनीति और अनुशासन लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में उच्च प्रदर्शन कार्यक्रमों का व्यापक अनुभव है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि टिम व्हाइट का अनुभव और उपलब्धियां जूनियर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी।

दर्पण विशेष

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवसः हर मां का हक है 'भयमुक्त' प्रसव और सुरक्षित जीवन

जीवन का चमत्कार अक्सर मातृत्व की यात्रा से शुरू होता है। यह अपार आनंद, आशा और माँ-बच्चे के बीच एक गहरे जुड़ाव का समय होता है। फिर भी, भारत में बहुत सी महिलाओं के लिए, जीवन देना ही एक खतरनाक अनुभव हो सकता है। मातृ मृत्यु का साया, यानी गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिला की दुखद मृत्यु, इस परिवर्तनकारी अनुभव पर गहरा प्रभाव डालती है। भारत में हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, इस गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे की याद दिलाता है। यह दिन गर्भावस्था और प्रसव के दौरान लाखों महिलाओं को होने वाले गंभीर जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आशा का दिन है, एक ऐसा आह्वान है जो हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां मातृत्व का अर्थ सुरक्षा और खुशहाली हो, न कि भय और हानि।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का इतिहास

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस केवल कैलेंडर पर एक निर्धारित तिथि नहीं है; यह राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में अंतर्निहित समर्पित प्रयासों का परिणाम है। इसके महत्व को समझने के लिए, हमें इसके इतिहास में गहराई से उतरना होगा, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किए गए जोशीले प्रयासों और निरंतर संघर्ष से चिह्नित है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की नींव 2000 के दशक की शुरूआत में रखी गई थी। उस समय भारत में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिससे मातृ स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। इस तात्कालिकता को समझते हुए, व्हाइट रिबन एलायंस इंडिया (हफ्शाक) आशा की किरण बनकर उभरा। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित 1800 से अधिक संगठनों के इस सशक्त गठबंधन ने मातृ कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। डब्ल्यूआरएआई की अथक पैरवी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं थी; यह प्रसव के खतरों का सामना कर रही अनगिनत महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के बारे में थी। उन्होंने व्यापक जागरूकता पैदा करने, कार्रवाई को गति देने और नीति निमार्ताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की मांग की। उनके प्रयासों का परिणाम 2003 में एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सामने आया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और डब्ल्यूआरएआई के अटूट समर्पण से प्रभावित होकर, भारतीय सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया। इस तिथि का विशेष महत्व था। यह महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती थी। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक कस्तूरबा गांधी पीढ़ियों के लिए आदर्श थीं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में चुनना मात्र प्रतीकात्मक नहीं था; यह उस महिला को एक सशक्त श्रद्धांजलि थी जिसने उन मूल्यों को साकार रूप दिया जिन्हें यह दिन बढ़ावा देना चाहता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की स्थापना करके, भारत मातृ स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दिन समर्पित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस कदम ने न केवल देश की सीमाओं के भीतर बल्कि पूरे विश्व में एक सशक्त संदेश दिया। इसने इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया और अन्य देशों को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं है; यह बदलाव का उत्प्रेरक है। महिलाएं इससे सुरक्षित गर्भावस्था संबंधी प्रथाओं के बारे में जान सकती हैं और ऐसी नीतियों की वकालत कर सकती हैं जो साल भर माताओं और नवजात शिशुओं के कल्याण को प्राथमिकता दें। हर गुजरते वर्ष के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की विरासत और मजबूत होती जा रही है, जो भारत में सभी महिलाओं के लिए मातृत्व को एक आनंदमय और सुरक्षित अनुभव बनाने वाले भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

क्यों महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आशा का एक सशक्त प्रतीक और कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह हमें मातृ मृत्यु दर की कठोर वास्तविकता का सामना करने और बदलाव के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आखिर यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए गहराई से जानें कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस दुनिया भर की माताओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम क्यों है। **वैश्विक संकट पर प्रकाशः** हर साल, अनुमानित 287,000 महिलाएं गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं से मर जाती हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 800 मौतें। ये आंकड़े भयावह तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इस वैश्विक संकट को उजागर करता है और हमें इसके विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये केवल संख्याएँ नहीं हैं; ये उन माताओं, बेटियों, बहनों और पत्नियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका जीवन असमय समाप्त हो जाता है। इस दिन के सम्मान में, हमें याद दिलाया जाता है कि मातृ मृत्यु अपरिहार्य नहीं है और हमें इन अनावश्यक मौतों को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। **स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच की मांगः** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता मातृ मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हमें इन असमानताओं का सामना करने और एक ऐसे विश्व की वकालत करने के लिए प्रेरित करता है जहां प्रत्येक मां, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान कुशल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके। इसमें प्रसवपूर्व देखभाल, आपातकालीन प्रसूति देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच शामिल है। इन असमानताओं को उजागर करके, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से वंचित समुदायों में। **परिवर्तन का उत्प्रेरकः** राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस केवल जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को संगठित करने तक सीमित नहीं है। यह दिन सरकारों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करने का एक मंच है झ सभी के लिए सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना। यह नीति निमार्ताओं को मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों और अवसंरचना विकास में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपने कौशल में सुधार करने और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। यह गैर-सरकारी संगठनों को शिक्षा और जागरूकता अभियान विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। अंततः, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक सामूहिक प्रयास को प्रेरित करता है जो महिलाओं को वह देखभाल प्राप्त करने से रोकती हैं जिसकी वे हकदार हैं। **मातृत्व और महिला सशक्तिकरण का उत्सवः** राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का मूल उद्देश्य मातृत्व का उत्सव मनाना है झ जो एक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। गर्भावस्था और प्रसव को सुरक्षित बनाने के प्रयासों से हम महिलाओं को इस यात्रा को आत्मविश्वास और आनंद के साथ जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। यह महिलाओं में आत्म-विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य और गर्भावस्था के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, मातृ मृत्यु दर को कम करके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाया जाता है, क्योंकि इससे उन माताओं की मृत्यु को रोका जा सकता है जो भावी पीढ़ियों के पालन-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। **भविष्य के लिए आशा की किरणः** हर माँ को सुरक्षित प्रसव के चमत्कार का अनुभव करने का अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आशा की किरण है, एक ऐसे भविष्य का वादा है जहाँ प्रसव किसी महिला के जीवन की कीमत पर न हो। यह एक ऐसा दिन है जब हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करते हैं जहाँ हर गर्भावस्था एक स्वस्थ माँ और बच्चे को जन्म दे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जागरूकता बढ़ाकर, कार्रवाई को प्रोत्साहित करके और मातृत्व का जश्न मनाकर माताओं, परिवारों और समुदायों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवसः भारत में सुरक्षित मातृत्व के लिए चल रहे संघर्ष पर एक नजर

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस (एनएसएमडी) का विशेष महत्व है। यह दिवस मातृ स्वास्थ्य की वकालत करने के लिए एक वैश्विक मंच है, लेकिन भारत का इस पर विशेष ध्यान देने से चर्चा में एक अनूठा आयाम जुड़ जाता है। यहां हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इस दिवस का इतना महत्व क्यों है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में मातृ मृत्यु दर (टटफ) एक गंभीर समस्या रही है। हालांकि हाल के वर्षों में देश ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और 2003 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 254 मौतों से घटकर 2020 में 181 (हल्ड के अनुमान) तक पहुँच गई है, फिर भी यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इस निरंतर चुनौती की याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह भारत को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने और आगे सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की स्थापना व्हाइट रिबन एलायंस इंडिया (हफ्शाक) के अथक प्रयासों का सीधा परिणाम थी। महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत 1800 से अधिक संगठनों के गठबंधनों ने मातृ मृत्यु दर को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस वकालत की शक्ति और उससे होने वाले सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में चुनने का एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व है। महात्मा गांधी की पत्नी, भारत के राष्ट्रपिता कस्तूरबा गांधी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कस्तूरबा गांधी सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थीं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में चुनना एक सशक्त श्रद्धांजलि है, जो मातृ स्वास्थ्य के लिए संघर्ष को महिलाओं के कल्याण के व्यापक संघर्ष से जोड़ती है। यह इस बात की निरंतर याद दिलाता है कि सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना केवल स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशिष्ट चुनौतियों का समाधान

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस केवल जागरूकता का दिन नहीं है; यह कार्रवाई के लिए एक प्रेरक शक्ति है। यह दिन देश में मातृ स्वास्थ्य को बाधित करने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इन चुनौतियों में शामिल हैं- **कुशल प्रसव सहायकों की सीमित उपलब्धताः** भारत में प्रसव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी घर पर या अपर्याप्त सुविधाओं वाले केंद्रों में होता है, अक्सर कुशल प्रसव सहायकों की अनुपस्थिति में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। **कुपोषण का समाधानः** भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो माताओं और नवजात शिशुओं दोनों को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उचित पोषण को बढ़ावा देता है, जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार हो सके। **स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से निपटनाः** गरीबी, शिक्षा का अभाव और सामाजिक कलंक मातृ स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इन सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने वाली पहलों को प्रोत्साहित करता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इन विशिष्ट चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करके जागरूकता को ठोस कार्य योजनाओं में परिवर्तित करता है। यह एक सशक्त मातृ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रगति का उत्सवः उपलब्धियों को मान्यता देना

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस केवल चुनौतियों को उजागर करने तक ही सीमित नहीं है; यह प्रगति का जश्न मनाने का भी अवसर है। हाल के वर्षों में देश ने मातृ मृत्यु दर (टटफ) में उल्लेखनीय कमी के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इन उपलब्धियों को स्वीकार करने और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में काम कर रहे सभी लोगों के प्रयासों को मान्यता देने का एक मंच है। यह मान्यता इस उपलब्धि को आशावाद से भर देती है। यह सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के रूप में प्रति लाख जन्मों पर टटफको 70 से नीचे लाने के समर्पण को प्रेरित करती है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस बहुआयामी उद्देश्यों को पूरा करता है। यह चुनौतियों पर चिंतन करने, आगे सुधार के लिए आह्वान करने और प्रगति का जश्न मनाने का दिन है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण ने उपायुक्तों से समाधान शिविर में आई समस्याओं को बिना विलंब समाधान करने के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

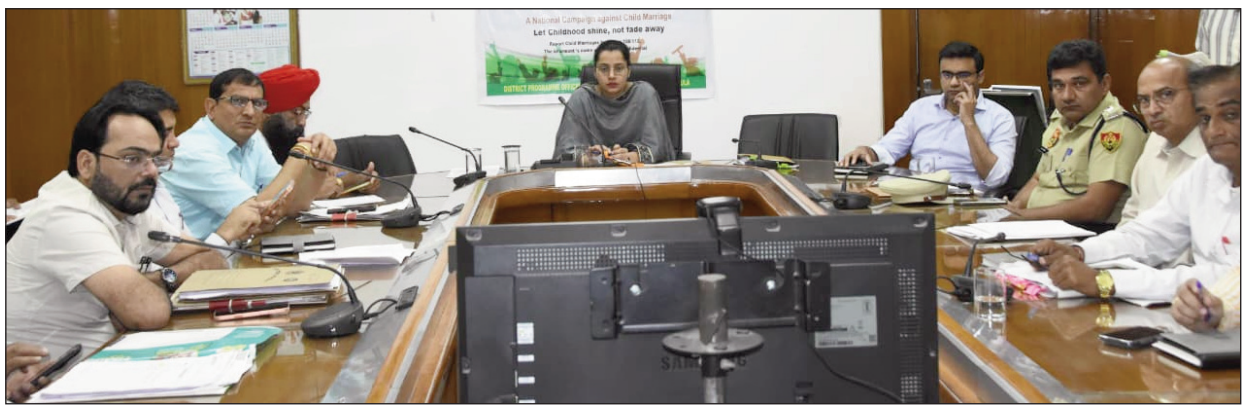

अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री विजेंद्र कुमार ने चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर में आई समस्याओं व लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को समाधान शिविर की समस्याओं व लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रमुखता से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को शेष बची समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया।

अतिरिक्त उपायुक्त ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों की समीक्षा की और जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिलावासी अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान न हों। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए अगली बैठक तक सभी विभाग अपनी-अपनी लंबित समस्याओं का समाधान करें ताकि जिला अव्वल स्थान प्राप्त कर सके।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए समाधान शिविर जिले में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं समाधान शिविर में आई लोगों की समस्याओं व अधिकारियों द्वारा किए गए समाधान की मोनिटरिंग करते है और स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविर से जुडते है। उन्होंने कहा कि जिलावासियों की समस्याओं का समाधान करना सभी अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में कोताही की गुंजाईश नहीं है।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, डीआरओ कुलदीप सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन जसमेर बंजारा, सत्यवान भारद्वाज, एसीपी अजीत सिंह, तहसीलदार सुरेश कुमार, पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की बैठक आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक श्री मंदीप सिंह बराड़, आईएएस, सचिव स्वास्थ्य, यू.टी. चंडीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित चल रही गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से एचआईवी के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को चंडीगढ़ के एआरटी केंद्रों से जोड़ने पर बल दिया गया। कम प्रदर्शन वाले संकेतकों पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मूल कारणों का विश्लेषण किया गया तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु ठोस रणनीतियों की पहचान की गई।

सचिव स्वास्थ्य, यू.टी. चंडीगढ़ ने निर्देश दिए कि दूसरे 95 लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सभी चिन्हित को शीघ्र एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से जोड़ा जा सके तथा उन्हें उपचार में बनाए रखा जा सके। साथ ही, नव-निदानित व्यक्तियों को पहले ही दिन परामर्श प्रदान करते हुए शीघ्र उपचार प्रारंभ करने और दीर्घकालिक अनुपालन के महत्व के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया गया, ताकि फॉलो-अप से छूटने की समस्या को कम किया जा सके। बैठक के दौरान, डॉ. सद्भावना पंडित, परियोजना निदेशक, ने कार्यक्रम के प्रदर्शन एवं प्रमुख रणनीतिक हस्तक्षेपों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें मौजूदा कमियों को रेखांकित करते हुए सुधार के लिए लक्षित उपाय सुझाए गए।

यह भी निर्देशित किया गया कि भारतीय चिकित्सा संघ के साथ समन्वय को सुदृढ़ किया जाए, ताकि निजी चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित कर निजी क्षेत्र में ढछल्लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सेवाओं की पहुंच का विस्तार किया जा सके। बैठक का एक प्रमुख आकर्षण रात्रि एड्स सुरक्षा अभियान पर प्रस्तुति रही, जो एक अभिनव रात्रिकालीन हस्तक्षेप रणनीति है। इसका उद्देश्य देर रात के समय संवेदनशील समूहों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसके लिए माइक्रोप्लानिंग एवं साझेदार गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मिशन एड्स सुरक्षा के अंतर्गत 95-95-99 लक्ष्यों की प्राप्ति एवं एचआईवी, सिफिलिस तथा हेपेटाइटिस-बी के ऊर्ध्वाधर संचरण के उन्मूलन से संबंधित राष्ट्रीय रणनीतिक पहल की जानकारी सभी सदस्यों के साथ साझा की गई। इस मिशन के अंतर्गत 1 दिसंबर 2026 तक 95-95-99 लक्ष्यों की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके। यह मिशन परीक्षण कवरेज बढ़ाने, उपचार से शीघ्र जोड़ने, वायरल लोड दमन में सुधार तथा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है, ताकि 1 दिसंबर 2027 तक एचआईवी महामारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष ने एचआईवी महामारी नियंत्रण की दिशा में प्रगति को तेज करने हेतु व्यापक जनसंपर्क, अधिक परीक्षण तथा सतत सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत प्रमुख पहलें एवं जागरूकता गतिविधियां

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों पर व्यापक जागरूकता एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया गया। आरसी धनास-2 में नवचेतना फ्रेमवर्क (0-3 वर्ष), मातृ पोषण के महत्व तथा शिशु एवं बाल आहार पद्धतियों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों, अधिकारियों एवं लाभार्थियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, दादू माजरा एवं इंडस्ट्रियल एरिया सर्किलों में भी पखवाड़ा मनाया गया, जहाँ माता-पिता एवं समुदाय की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए स्क्रीन टाइम को कम करने, दैनिक आहार एवं व्यक्तिगत देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। इसके साथ ही विभिन्न विषयगत गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं, जिनमें शीघ्र स्तनपान को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं के लिए मोटे अनाज (मिलेट्स) आधारित पोषण, बच्चों की वृद्धि निगरानी, 3झ6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा, तथा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु गृह भ्रमण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, खाद्य सुदृढ़ीकरण (फोर्टिफिकेशन), पोषण के पंच सूत्र तथा पूरक आहार पद्धतियों पर सत्र आयोजित किए गए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मिलेट्स को आहार में शामिल करने पर भी विशेष बल दिया गया। आगे, आयुष चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन पोषण हेल्पलाइन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से लाभार्थियों को चिकित्सकों से सीधे संवाद कर पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

यू.टी. सचिवालय में श्री मंदीप सिंह बराड़, सचिव स्वास्थ्य, यू.टी. चंडीगढ़ प्रशासन की अध्यक्षता में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कार्यों की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त सचिव स्वास्थ्य, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-सह-मिशन निदेशक नोडल अधिकारी तथा सभी अअट२ एवं वअअट२ के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज उपस्थित रहे। बैठक में यह रेखांकित किया गया कि अअट२ एवं वअअट२ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और लाभार्थियों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं। अतः इन संस्थानों को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों पर भार कम किया जा सके।

बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से उनके-अपने केंद्रों में चिन्हित कमियों, कार्यभार एवं लागू किए जा रहे नवाचारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यक्षेत्र, रोगी भार, चुनौतियों तथा सेवा सुधार हेतु अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य सचिव ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पेपरलेस बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, सभी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि वे मरीजों, विशेषकर वृद्ध/जराचिकित्सा (जेरियाट्रिक) रोगियों के साथ विनम्र एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करें। साथ ही, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक सूची के अनुसार दवाओं एवं जांच सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

संक्षिप्त-समाचार

अनियमितता की शिकायत के बाद केमिस्ट शॉप पर छापेमारी, अवैध दवाइयां जब्त की

चंडीगढ़। मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन (यू.टी.) के निदेर्शों तथा सचिव स्वास्थ्य एवं निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, यू.टी. प्रशासन के मार्गदर्शन में, श्री तजिंदर सिंह, ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग्स कंट्रोल विभाग, चंडीगढ़ द्वारा केमिस्ट शॉप कपूर मेडिकोस, बूथ नं. 119, सेक्टर 40-सी, चंडीगढ़ पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 540 टैबलेट तथा 10 गर्भपात किट को खरीद एवं बिक्री रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के कारण जब्त किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म के परिसर की जांच की गई तथा विभिन्न आदत बनाने वाली दवाओं के रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय योग्य फार्मासिस्ट/प्राधिकृत व्यक्ति अनुपस्थित पाया गया तथा फर्म द्वारा खरीद एवं बिक्री का आवश्यक रिकॉर्ड भी संधारित नहीं किया जा रहा था। फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है तथा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

टीबी मुक्त भारत – 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत मॉडल जेल, बुरैल में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन

चंडीगढ़। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मॉडल जेल, बुरैल में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2026 तक एक सप्ताह का आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान सभी बंदियों को क्षय रोग (टीबी) के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें इसके लक्षण, संक्रमण के तरीके तथा सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क जांच एवं उपचार सेवाओं की जानकारी दी गई। शीघ्र पहचान एवं त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए बंदियों की ऑन-द-स्पॉट स्क्रीनिंग हैंडहेल्ड डिजिटल एक्स-रे मशीनों के माध्यम से की गई, साथ ही उइठअअळ तकनीक द्वारा स्पुटम जांच भी की गई। यह पहल चंडीगढ़ प्रशासन की टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान एवं प्रभावी उपचार सेवाओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है, विशेषकर संवेदनशील वर्गों के बीच, जिससे टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान मिल सके।

फतेहपुर राजकीय बाग में सरप्लस फलों की नीलामी 17 अप्रैल को

पंचकूला। जिला के अंतर्गत राजकीय बाग एवं नर्सरी, फतेहपुर पर उपलब्ध सरपल्स फलों जैसे आम, चीकू, लिची, नाशपति, अमरूद व जामुन आदि फलों की नीलामी वितिय वर्ष 2026 के लिए 17 अप्रैल 2026 को दोपहर ढाई बजे की जाएगी। यह नीलामी निदेशालय द्वारा नियुक्त अधिकारी की देखरेख में पूरी पारदर्शी तरीके से आयोजित होगी। जिला उद्यान अधिकारी डॉ अशोक कौशिक ने बताया कि फलों की नीलामी खुली बोली के आधार पर की जाएगी। उन्होने बताया कि नीलामी से पहले बाग को देखने के लिए इच्छुक व्यक्ति, ठेकेदार अथवा फर्म किसी भी कार्यदिवस में राजकीय बाग एवं नर्सरी फतेहपुर में आकर बाग का निरिक्षण कर सकते हैं। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता को 50 हजार रुपए अग्रिम धरोहर राशि के तौर पर जमा करवानी होगी जो कि सफल बोलीदाता के अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को नीलामी के बाद वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि को नीलामी की राशि की पहली किस्त में समायोजित कर दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों के पास आधार कार्ड की मूल प्रति होना अनिवार्य है। नीलामी के लिए बाग का क्षेत्र लगभग 15 एकड़ है। नीलामी की अन्य शर्तें मौके पर बताई जाएंगी। उन्होंने बताया कि नीलामी के दिन दोपहर 1 बजकर 30 मिनट के बाद नर्सरी पर पहुंचने वाले किसी भी प्रतिभागी से अग्रिम राशि स्वीकार नही की जाएगी एवं न ही उन्हें नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। डॉ अशोक कौशिक ने आमजन से बोली प्रक्रिया में बढचढ कर भाग लेने की अपील की है । उन्होने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

पलवल में 15,000 की रिश्वत लेते क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई

पलवल। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद पलवल के एक क्लर्क सुनील कुमार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद में एफआईआर संख्या 07 दिनांक 10.04.2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता धर्म सिंह ने एसीबी को शिकायत दी थी कि नगर परिषद पलवल में कार्यरत क्लर्क सुनील कुमार, जो अतिरिक्त रूप से पटवारी का कार्य भी देख रहा था, उससे उसकी जमीन को नगर परिषद सीमा में न दिखाने के एवज में 15,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी, पलवल इकाई की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। इस दौरान आरोपी सुनील कुमार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया गया। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख ए एस चावला ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सशक्त नेतृत्व में हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है। एसीबी प्रमुख ने आमजन से आग्रह किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर-1800 180-2022 को दें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता के सहयोग से ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा का निर्माण संभव है।

विरासत फेस्ट का धमाकेदार समापन, गिप्पी ग्रेवाल के लाइव कॉन्सर्ट में मचा धमाल, झूमा पूरा कैंपस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

विरासत फेस्ट 2026 का समापन इस बार सचमुच यादगार बन गया, जब गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 का कैंपस संगीत, ऊर्जा और उत्साह के रंगों में डूब गया। दो दिनों तक चला यह फेस्ट अपने अंतिम दिन एक भव्य कॉन्सर्ट में तब्दील हो गया, जहां मशहूर पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल की धमाकेदार प्रस्तुति ने माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। जैसे ही गिप्पी ग्रेवाल मंच पर आए, हजारों छात्रों की भीड़ झूम उठी और पूरा कैंपस तालियों और उत्साह से गूंजने लगा। हर तरफ सिर्फ संगीत, मस्ती और जश्न का माहौल नजर आया।

ग्रैंड फिनाले में ह्यमिस विरासतह्ल और ह्यमिस्टर विरासतह्ल के खिताबों ने कार्यक्रम में ग्लैमर का तड़का लगाया। अनमोल ने ह्यमिस्टर विरासतह्ल और भगवान कौर ने ह्यमिस विरासतह्ल का ताज अपने नाम किया। वहीं रुद्र और दीक्षा ह्यमिस्टरह्ल और ह्यमिस इनसाइटह्ल बने, जबकि अक्षत और सीमिता ह्यमिस्टरह्ल और ह्यमिस रीगलह्ल घोषित किए गए। कार्यक्रम के दौरान शिवा चौधरी की प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का उत्साह चरम पर बनाए रखा।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चंडीगढ़ प्रशासन की शिक्षा व खेल सचिव प्रेरणा पुरी ने शिरकत की। उन्होंने आयोजन के भव्य स्तर, छात्रों के उत्साह और अनुशासन की सराहना करते हुए इसे एक प्रेरणादायक सांस्कृतिक मंच बताया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि दो दिनों तक चला यह उत्सव छात्रों की प्रतिभा और ऊर्जा का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। उन्होंने कहा कि विरासत फेस्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि सांस्कृतिक मंच पूरे कैंपस को एकजुट कर रचनात्मकता का उत्सव बना सकते हैं। संगीत की गूंज, चेहरे पर मुस्कान और दिलों में उमंग के साथ विरासत फेस्ट 2026 का समापन हुआ—एक ऐसा उत्सव, जिसकी यादें अब अगले वर्ष तक सबके साथ रहेंगी।

मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अब तक 5358 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद तथा 427 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की आवक शुरू होने के साथ खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 5358 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 427 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुरानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुरानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 428 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 904 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1050 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 2800 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 176 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई।

उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 59 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 117 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 125 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 126 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा से डेनमार्क तक: एचपीवी से जुडी गलत सूचना पर शोध को मिली वैश्विक पहचान

सिटी दर्पण संवाददाता
बठिंडा

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन विभाग के अध्यक्ष एवं इंटरवेंशन्स डिजाइन एंड इफेक्ट्स लैब (आई.डी.ई.एल.) के संस्थापक डॉ. रुबल कानोजिया तथा उनके पीएचडी शोधार्थी सुश्री रक्तिमा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। उनका शोध पत्र डेनमार्क के ओडेंस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क में 13झ15 अप्रैल 2026 को आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार सम्मेलन में प्रस्तुति हेतु चयनित हुआ है।

भारत में एचपीवी टीकाकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शोध समाज में फैली गलत सूचनाओं को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से कैंसर की रोकथाम के प्रयासों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। परसीव्ड बैरियर्स टू एचपीवी प्रिवेंटिव केयर अमंग सेक्सुअल एंड जेंडर माइनॉरिटीज इन इंडियाः ए क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेशन शीर्षक वाले इस शोध में यह उजागर किया गया है कि एचपीवी के प्रति जागरूकता की कमी, एचपीवी और उसके टीके के बारे में अपर्याप्त जानकारी, आर्थिक बाधाएं, समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता तथा जनसामान्य में फैली गलत सूचनाएं एचपीवी से बचाव में प्रमुख अवरोध हैं।

शोधकताओं के अनुसार इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि गलत सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, एचपीवी और उसके टीके के प्रति सही जानकारी का प्रसार, जनजागरूकता अभियानों को सशक्त बनाना तथा स्वास्थ्यकर्मियों को संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी वर्गों को समावेशी और समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस अवसर पर सीयू पंजाब के कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने डॉ. रुबल कानोजिया और सुश्री रक्तिमा गुप्ता को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि आई.डी.ई.एल. लैब से स्वास्थ्य संचार के क्षेत्र में लगातार हो रहे शोध यह दर्शाते हैं कि सामाजिक विज्ञान शोध न केवल समाज की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकता है, बल्कि नीति-निर्माण और वैश्विक शैक्षणिक विमर्श में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

डॉ. रुबल कानोजिया ने बताया कि आई.डी.ई.एल. लैब देश की शुरूआती प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं में से एक है, जो जनसंचार के क्षेत्र में रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल (आरसीटी) और क्वासी-एक्सपेरिमेंटल शोध को समर्पित है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कुलपति प्रो. तिवारी के मार्गदर्शन, प्रेरणा और निरंतर सहयोग को दिया, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय में सशक्त शोध वातावरण विकसित हो रहा है। उनके प्रयासों से सीयू पंजाब ने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

इस उपलब्धि को और मजबूती देते हुए आई.डी.ई.एल. लैब के कैंसर संबंधी गलत सूचनाओं पर किए गए हालिया शोध को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा स्वीकार किया गया है। एचपीवी टीके से संबंधित गलत सूचनाओं पर यह शोध भी विश्वविद्यालय के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है। आई.डी.ई.एल. लैब के अन्य सदस्यों सुश्री ऋतु आर्या (एसआरएफ), श्री नमन घनघस, श्री रॉबिन जिंदल, श्री रगेंदु आर. एवं श्री अमित शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता मजबूत शोध संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने जनस्वास्थ्य संचार के क्षेत्र में गलत सूचनाओं को दूर करने, प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करने और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह उपलब्धि सी यू पंजाब के जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन विभाग की बढ़ती शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक शोध सहभागिता को भी दशार्ती है।